

RNI No. GUJHIN/2010/35230

महानगर मेट्रो

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र

कार्यालय :- सी-8 रिची हाउस, स्वामी नारायण मंदिर के सामने मणिनगर अहमदाबाद गुजरात-380008

महानगर मेट्रो
राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, प्रेस नोट एवं विज्ञापन के लिए कार्यालय पर सम्पर्क करें
सरबजीत माकन
+91-9638877700
mahanagarmetro7@gmail.com

वर्ष :15 । अंक:320। पेज:12। mahanagarmetro7@gmail.com || अहमदाबाद,11 जुलाई 2026 (शनिवार) || सम्पादक - सरबजीत माकन (9638877700)।। मूल्य :- 1.50 रु.-/

समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत

आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत 'INS महेंद्रगिरि', ब्रह्मोस से होगा लैश



एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की ताकत में शनिवार को एक और बड़ा इजाफा होने जा रहा है. भारत में ही बना अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि (F38) कल विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.

पूर्वी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के नाम पर बने 'INS महेंद्रगिरि' को भारतीय नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' ने डिजाइन किया है और इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने तैयार किया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस जंगी जहाज को बनाने में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामान और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है.

इस फ्रिगेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार, थर्मल या इंफ्रारेड सेंसर इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे. यानी यह समंदर में छिपकर दुश्मन पर वार करने में माहिर है.

मिसाइलों और घातक हथियारों से है लैस

प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह छठा स्वदेशी युद्धपोत हवा, सतह और समंदर के भीतर (पनडुब्बी विरोधी) तीनों तरह के ऑपरेशन्स को एक साथ संभालने की ताकत रखता है. यह जहाज अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें शामिल हैं :

ब्रह्मोस: सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल.
हवा में दुश्मन को ढेर करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम (बराक-8).
आधुनिक सेंसर, रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम.

भारतीय नौसेना में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि शामिल होने को तैयार है. 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत दुश्मन की रडार से बचकर वार करने में सक्षम है.

पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने वाले एंटी-सबमरीन हथियार.

क्यों खास है यह कमिशनिंग?

INS महेंद्रगिरि का शामिल होना प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम में एक और अहम मील का पत्थर है. जैसे-जैसे इस क्लास के और फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल होंगे, उम्मीद है कि वे भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को और बढ़ाएंगे, साथ ही एक लीडिंग स्वदेशी वॉरशिप-बिल्डिंग देश के तौर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे.

भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है कि हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक रीजन में बढ़ते रणनीतिक खतरों के बीच INS महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' साबित होगा. यह न सिर्फ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा बल्कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभाएगा.

इजराइल-अमेरिका जैसी होगी भारत की हर सीमा, क्या है अमित शाह का 'क्वाड्रैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' प्लान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत सरकार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'क्वाड्रैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' का ऐलान करते हुए साफ किया कि अब सीमा सुरक्षा केवल जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य पुलिस, नागरिक प्रशासन और सीमावर्ती लोगों की भागीदारी के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य भारत की सीमाओं को इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर पूरी तरह तकनीक आधारित और अभेद्य बनाना है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट सेंसर, थर्मल निगरानी और एकीकृत सुरक्षा नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर में 400 प्रतिशत बढ़ोतरी, भारत-म्यांमार सीमा पर करीब 1,610 किलोमीटर लंबी फेंसिंग और सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी पर नजर रखने जैसी योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इन कदमों से घुसपैठ, ड्रोन के जरिये हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से होने वाले अन्य सुरक्षा खतरों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी.



14 महीने में 7 IPS का इस्तीफा, इनमें 6 की उम्र 40 से कम...सिंघम की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते अफसर?

एजेंसी

नई दिल्ली। आईपीएस अधिकारियों के लगातार इस्तीफों के कारण इंडियन पुलिस सर्विस सुर्खियों में है. ताजा मामला ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी जगमोहन मीणा का है. 37 वर्षीय जगमोहन भुवनेश्वर में डीसीपी के पद पर तैनात थे. अब उन्होंने चुपचाप अपना इस्तीफा भेज दिया है. जगमोहन इंडियन पुलिस सर्विस के सातवें अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले 14 महीनों में इस्तीफा दिया है. यह तब हो रहा है, जब पुलिस सेवा में 500 से अधिक पद रिक्त हैं.



फरवरी 2026 में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री (पीएमओ) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया था कि आईपीएस के 505 पद अभी रिक्त हैं. इसी साल की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आईपीएस अधिकारियों की कमी के कारण आईबी और सीबीआई में 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं.

1 अगस्त से ष्ठअष्ट बसों में पिंक टिकट बंद, महिलाओं को अब बनवाना होगा 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'

नोएडा। दिल्ली में 1 अगस्त से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (ष्ठञ्जष्ट) बसों में पिंक टिकट बंद होगी. 1 अगस्त से ष्ठञ्जष्ट बसों में पिंक सहेली ह्यष्टस्रष्ठ कार्ड के जरिए ही महिलाएं मुफ्त सफर कर पाएंगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक अभी तक दिल्ली में 15 लाख पिक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1 अगस्त के बाद भी अलग-अलग सेंटर पर इनको बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी.



दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त से ष्ठञ्जष्ट की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को फ्री बस सफर स्कीम का फायदा उठाते रहने के लिए जरूरी तौर पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखना और टैप करना होगा.

रेखा गुप्ता सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उसने मौजूदा पेपर-बेस्ड पिंक टिकट को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है.

जाएगी सरकारी नौकरी, योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ... असम में बहुविवाह पर सख्त कानून

असम सरकार ने बहुविवाह के दोषी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का प्रस्ताव किया है.

नई दिल्ली। असम सरकार ने शुक्रवार को एक से ज्यादा शादी करने के दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि एक से ज्यादा शादी करने वाले लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत फायदे नहीं उठा पाएंगे. पीटीआई न्यूज के मुताबिक, बरुआ ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए, एक से ज्यादा शादी करने वाला कोई भी पुरुष किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत फायदे पाने के लायक नहीं होगा.



बजट में असम सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1964 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि एक से ज्यादा शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कानून के मुताबिक नौकरी से निकाला जा सके.

बरुआ ने आगे कहा, ÷ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी क्रिमिनल लॉ के तहत किसी भी जुर्म के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति नोटिफाइड सरकारी वेलफेयर स्कीम के तहत फायदे पाने के लायक नहीं होगा.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर पेपर लीक तक...कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने BJP पर साधा निशाना

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं से मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करने का आग्रह किया और कहा कि पार्टी की एकता 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, इसलिए वो सरकार बदलना चाहते हैं.

एजेंसी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीते बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग-अलग नेताओं से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 'मुझे खुशी है कि यहां सभी नेता चुनावों में पूरी मजबूती के साथ लड़ने को तैयार हैं और हम जीतेंगे. हमने कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक की. ष्ठष्टष्ट अध्यक्षों के साथ चार घंटे तक बैठक चली. साथ ही हमने मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ भी मीटिंग की'.

उन्होंने आगे कहा, 'उत्तराखंड के लोग ञ्छष्ठक्क सरकार से निराश हैं, वो गुस्से में हैं. वो चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए और हम जनता के साथ मिलकर यहां परिवर्तन लाएंगे. उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी से परेशान है और पलायन कर रहा है. ऐसे में सवाल है कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी कम करने और पलायन रोकने के लिए क्या किया? भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है. बीजेपी के विधायक तक कहते हैं कि यहां कमीशन लिया जाता है और खुद सीएम इसे बढ़ावा दे रहे हैं. इन सभी मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावों में उतरेगी, क्योंकि हम यहां की जनता और युवाओं के साथ खड़े हैं'.



केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बिना किसी मतभेद के लड़ेगी और हम निर्णायक जीत हासिल करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ष्टक्कक्ष चेयरपर्सन सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हम राज्य में आगामी चुनाव जीतेंगे.

NEET पेपर लीक को लेकर क्या कहा?

एआईसीसी के महासचिव ने ह्यश्वश्वञ्ज पेपर लीक और सीबीएसई में हुई गड़बड़ियों को लेकर कहा कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि 'छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं. बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं. उत्तराखंड अब पेपर लीक घोटालों के लिए जाना जाने लगा है. इसलिए कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाएगी. हम एक घोषणापत्र समिति बना रहे हैं और वो राज्य भर में घूमकर आम लोगों, जिनमें किसान, महिलाएं और छात्र शामिल हैं, उनसे मुद्दे इकट्ठा करेंगे. फिर हम उत्तराखंड के लिए एक मजबूत और व्यापक घोषणापत्र तैयार करेंगे'.

ममता की बढ़ी मुश्किलें, टीएमसी के 12 और बैंक अकाउंट फ्रीज

एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और ञ्जब्रत बनर्जी की टीएमसी के बीच असली टीएमसी की जंग तेज हो गयी है. गुरुवार को तीन अकाउंट्स के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद ममता बनर्जी समर्थक तृणमूल कांग्रेस पर फिर से दबाव बढ़ गया है. पुलिस ने एक साथ 12 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं.

पता चला है कि ये अकाउंट्स जांच के लिए फ्रीज किए गए हैं. ञ्जब्रत गुट के एक तृणमूल विधायक ने शुरू में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए



शिकायत दर्ज कराई थी. उसी आधार पर पहले तीन और अब 12 अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं.

करीब 1000 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन पर रोक

राज्य पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के मकसद से 12 नए बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए संबंधित प्राइवेट और सरकारी बैंकों में अर्जी दी गई थी. पुलिस की रिक्वेस्ट पर बैंक अधिकारियों ने उन्हें फ्रीज कर दिया है.

कुल मिलाकर, पुलिस ने अब तक कुल 15 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं. इनमें से तृणमूल फिलहाल तीन का इस्तेमाल कर पा रही है. राज्य पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 15 बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. नए फ्रीज किए गए 12 अकाउंट के बारे में संबंधित बैंक अधिकारियों से डिटेल्ड जानकारी मांगी गई है.

बूटलेगरों के शिकंजे में करजणः देसी-विदेशी शराब और जुए के अड्डों की बाढ़

पर एसपी सुशील अग्रवाल और पीआई पटेल मौन, जेल रिटर्न 'वहीवटदार' के आगे पूरा पुलिस तंत्र नतमस्तक, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी को खुली चुनौती

महानगर मेट्रो विशेष ब्यूरो रिपोर्ट

गुजरात में कागजी शराबबंदी के उड़े परखच्चे; थानों से महज 2 किमी की दूरी पर धधक रही हैं अवैध भट्टियां, मुखबिर तंत्र हुआ फेल

महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

करजण/वडोदरा। गुजरात सरकार और सूबे का गृह विभाग भले ही पूरे राज्य में कड़े कानून और सख्त शराबबंदी के आसमान छूते दावे करता हो, लेकिन वडोदरा जिले के करजण तालुका से जो चौंकाने वाली कड़वी हकीकत सामने आई है, उसने गांधीनगर में बैठे आला अफसरों की नींद उड़ा दी है। करजण में कानून और व्यवस्था के सरेआम चिथड़े उड़ रहे हैं। पूरा तालुका बूटलेगरों और जुआरियों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका है। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर करजण पुलिस थाने की नाक के नीचे करोड़ों रुपये का अवैध नेटवर्क धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे ज्यादा हैरान और शर्मसार करने वाली बात यह है कि इस पूरे काले साम्राज्य की कमान किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि खुद पुलिस के ही एक खासमखास 'वहीवटदार' (बिचौलिया) के हाथ में है, जो पहले भी शराब के संगीन मामलों में जेल की हवा खा चुका है।

गांव-गांव में शराब की नदियां और सट्टे के अड्डेः लोकेशन के साथ बड़ा भंडाफोड़

विश्वस्त सूत्रों से मिली बेहद पुख्ता और सनसनीखेज जानकारी के मुताबिक, करजण पुलिस स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करमडी गांव में इस समय कम से कम 15 से ज्यादा देसी शराब की अवैध भट्ठियां धधक रही हैं, जहां से पूरे इलाके में जहर की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा, कुलारी गांव में नई नगरी स्थित पानी की टंकी के पास नगीन नाम का नामी बूटलेगर बिना किसी खौफ के खुलेआम 'वरली-मटका' का सट्टा बाजार चला रहा है। सापा गांव की नई वसाहत (बस्ती) में भी सट्टे का यह धंधा चरम पर है। इतना ही नहीं, सत्ताधारी दल के रसूख का एक और बड़ा नमूना देखिए; राणपुर गांव का सरपंच और बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पार्थ शाह खुद पूरे करजण तालुका में विदेशी (इंग्लिश) शराब का बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। सूचना तो यहां तक है कि सीमडी गांव से राणपुर गांव जाने वाले गुप्त रास्ते पर विदेशी शराब का बहुत बड़ा जखीरा छिपाकर रखा गया है। वहीं कंडारी गांव की सोसाइटी नंबर 2 के टावर के पास वेमरडी रोड पर अमित वसावा नाम का शख्स धड़ल्ले से विदेशी शराब बेच रहा है, जबकि बारियावास और बारिया वगो इलाके में परेश चूनावाड़ा नाम का तस्कर खुलेआम अंग्रेजी शराब की खेप खपा रहा है।

जेल रिटर्न वहीवटदार हनुभा कामड़िया का खौफः काले धंधे से बनाई अकूत संपत्ति

इस पूरे सिंडिकेट और अवैध कारोबार के पीछे करजण पुलिस स्टेशन के पीआई पटेल का सबसे चहेता और खास वहीवटदार हनुभा कामड़िया उर्फ हनु बूटलेगर मुख्य मास्टरमाइंड है। यह हनुभा कोई दूध का धुला नहीं है, बल्कि पहले भी शराब के बहुत बड़े मामले में पकड़ा जा चुका है, पुलिस महकमे से सस्पेंड हुआ था और जेल में भी दिन काट चुका है। ऐसे शातिर और रीढ़े अपराधी ने आज पूरे करजण तालुका की पुलिस को अपनी जेब में रखकर पूरी व्यवस्था को बंधक बना लिया है। शराब और जुए के अड्डों से होने वाली करोड़ों रुपये की काली कमाई के दम पर इस बिचौलिए ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और करोड़ों रुपये की बेनामी हराम की संपत्तियां खड़ी कर ली हैं। वडोदरा जिले के पुलिस कप्तान (SP) सुशील अग्रवाल, वडोदरा एलसीबी (LCB) और करजण पुलिस के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का मुंह इस कथित वहीवटदार हनुभा ने पैसे की हनक पर पूरी तरह से बंद कर दिया है।



गृहमंत्री हर्ष संघवी को खुली चुनौतीः क्या एलसीबी सिर्फ हफ्ता वसूली में मगन है?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कोई जागरूक नागरिक गांधीनगर की स्टेट मॉनिटरिंग सेल में इन अड्डों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराता है। गांधीनगर से स्पेशल टीम की छापेमारी होने से पहले ही वडोदरा एलसीबी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हनुभा और करजण पीआई पटेल को व्हाट्सएप पर लोकेशन और मैसेज भेजकर अलर्ट कर देते हैं कि 'गांधीनगर की गाड़ी रवाना हो चुकी है, अपने-अपने अड्डे तुरंत बंद कर लो!' ऐसा लगता है कि वडोदरा एलसीबी को अब केवल और केवल लाखों रुपये के मासिक हफ्तों की उगाही में ही दिलचस्पी रह गई है। यह पूरी भ्रष्ट चौकड़ी राज्य के मुख्यमंत्री की बेदाग छवि पर कालिख पोत रही है और गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी के नशामुक्त गुजरात अभियान को खुलेआम ठेंगा दिखा रही है। 'महानगर मेट्रो' सीधे शब्दों में सरकार से सवाल पूछता है कि बूटलेगरों के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे पुलिसिया वर्दीधारियों पर गांधीनगर का हंटर कब चलेगा? क्या करजण की भोली-भाली जनता को इस नशे और जुए के दलदल से कभी मुक्ति मिल पाएगी?

डोंगरगढ़ के खिलाड़ियों को मिले आधुनिक खेल सुविधाएं, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मिला प्रतिनिधिमंडल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

डोंगरगढ़। धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी डोंगरगढ़ आज केवल मां बम्लेश्वरी की पावन नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं की उभरती हुई भूमि के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बना रही है। नगर के युवा खिलाड़ी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिला, संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित कर रहे हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर उन्होंने डोंगरगढ़ तथा पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। इसके बावजूद नगर में आधुनिक खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण केंद्र, इंडोर एवं आउटडोर खेल परिसर, रनिंग ट्रैक, जिम, खेल उपकरण तथा प्रशिक्षकों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन्हीं महत्वपूर्ण मांगों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे के नेतृत्व में डोंगरगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें नगर की खेल गतिविधियों, खिलाड़ियों की उपलब्धियों तथा खेल सुविधाओं की वर्तमान स्थिति से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डोंगरगढ़ के खिलाड़ी एथलेटिक्स, कराटे जिजिसु कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सहित अनेक खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक और सम्मान प्राप्त किए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह साबित करता है कि यदि उन्हें आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. रमन सिंह से आग्रह किया कि डोंगरगढ़ में एक आधुनिक खेल परिसर, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सुसज्जित खेल मैदान, रनिंग ट्रैक, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, नियमित प्रशिक्षकों की नियुक्ति तथा आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनेक खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक संसाधनों दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यदि ये सुविधाएं डोंगरगढ़ में विकसित हो जाएं तो क्षेत्र के हजारों युवाओं को अपने ही नगर में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सकेगा और खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी। डॉ. रमन सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि डोंगरगढ़ में खेल प्रतिभाओं की उपलब्धियां पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय हैं। उन्होंने माना कि खिलाड़ियों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि उनकी प्रतिभा को उचित मंच मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि खेल सुविधाओं के विकास के संबंध में संबंधित विभाग से शीघ्र पत्राचार किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार खिलाड़ियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करेगी। मुलाकात के दौरान डोंगरगढ़ राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने समाज भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग की मांग भी रखी।



मोडासा में नगर पालिका का बुलडोज़रः कॉलेज रोड से 24 कच्चे और पक्के निर्माण हटाए गए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मोडासा। मोडासा में कॉलेज रोड के छपरा इलाके में नगर पालिका द्वारा अचानक निर्माण हटाने की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सड़क चौड़ी करने के मकसद से प्रशासन ने बड़े पैमाने पर 24 कच्चे और पक्के निर्माणों को गिरा दिया। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा होकर विरोध करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार, बालापीर को पहाड़पुर से जोड़ने वाली यह कॉलेज रोड पहले R&B राज्य विभाग के नियंत्रण में थी, जिसे कुछ समय पहले R&B पंचायत विभाग को सौंप दिया गया था। R&B राज्य विभाग ने सबसे पहले 2011 में इस सड़क पर बरसों से रह रहे लोगों को निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया था। फिर 2023 में, R&B पंचायत विभाग ने निवासियों को फिर से नोटिस भेजा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नए नोटिस में 6 मीटर का कोई ज़िक्र नहीं था। हालांकि, नगर पालिका ने सड़क को सीधे 9 मीटर का माना और उसके दायरे से बाहर के सभी निर्माणों को गिरा दिया। इस संबंध में वार्ड-7 के पार्षद जी.आई. खलक ने कहा कि प्रभावित निवासियों के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय में इस मामले को उठाया जाएगा। निवासी सवाल उठा रहे हैं कि अगर 2011 में 6 मीटर तय किया गया था, तो अचानक इसे 9 मीटर कैसे माना जा सकता है.



अधिकारियों को देखकर डंपर ड्राइवरों ने चलती गाड़ी से सड़क पर रेत गिराई और फ़िल्मी अंदाज़ में भाग निकले



महानगर मेट्रो ब्यूरो

इडर। इडर तालुका में साबरकांठा ज़िले के मिनरल माफिया के बेरहम और बेखौफ़ होने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अधिकारियों की पकड़ से बचने के लिए, रेत चोरों ने सारी हदें पार कर दीं; उन्होंने चलती गाड़ी से सड़क पर रेत गिराई और फ़िल्मी अंदाज़ में भाग निकले। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और चर्चा का विषय बन गया है, वहीं दूसरी ओर, जियोलॉजिस्ट और पुलिस के बयानों में बड़ा विरोधाभास कई सवाल खड़े कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, माइनिंग डिपार्टमेंट को इडर तालुका के चोडाप और हाडोल गांवों के बीच बहने वाली साबरमती नदी के तल से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन की सूचना मिली थी। इस जानकारी के आधार पर, साबरकांठा ज़िले के जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने आज सुबह उस इलाके में छापा मारा। सरकारी गाड़ियों को देखकर, अवैध रूप से रेत भर रहे डंपर ड्राइवर घबरा गए और तेज़ी से भागने लगे। अधिकारियों की गाड़ी ने रेत चोरों का पीछा किया। लेकिन, जब माफिया को लगा कि वे अब कानून की पकड़ में आ जाएंगे, तो उन्होंने गांव की मुख्य सड़क पर एक खतरनाक चाल चली। गांव में घुसते ही, डंपर ड्राइवरों ने चलती गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठाया और सड़क के बीचों-बीच रेत का ढेर गिरा दिया! माफिया का मकसद पीछे आ रही अधिकारियों की गाड़ियों को रोककर अपना रास्ता साफ़ करना था, जिसमें वे कामयाब भी रहे। जब चोडाप और हाडोल गांवों के बीच मुख्य सड़क पर यह हाई-वोल्टेज ड्रामा और पीछा करने का सिलसिला चल रहा था, तब वहां से गुज़र रहे मासूम स्कूली छात्र, दिव्यांग बुजुर्ग और ग्रामीण बाल-बाल बचे। अगर ज़रा सी भी चूक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था और मासूम लोगों की जान जा सकती थी। सरकारी गाड़ी देखकर डंपर ड्राइवर तेज़ी से भागने की कोशिश करने लगा। हमने इस मामले में इडर पुलिस स्टेशन में कानूनी शिकायत भी दर्ज कराई है।

वडोदरा में सत्ताधारियों का अंधा आतंक

नर्मदा मैया का चीरहरण और डेयरी में लाखों की लूट, फिर भी कलेक्टर-एसपी नतमस्तक

महानगर मेट्रो विशेष ब्यूरो

मुख्यमंत्री के 'जीरो टॉलरेंस' के दावों की उड़ी धज्जियां; सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक भ्रष्टाचार का खुला खेल

वडोदरा में अवैध खनन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से सियासत गरम

महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

वडोदरा/करजण। गुजरात सरकार भले ही गांधीनगर की गद्दी से 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' और 'भ्रष्टाचार मुक्त शासन' के बड़े-बड़े दावे ठोकती हो, लेकिन वडोदरा जिले से सामने आई जमीनी हकीकत सत्ताधारी दल और सरकारी तंत्र के दावों की धज्जियां उड़ाने वाली है। जिले में सरपंच की कुर्सी से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद तक भ्रष्टाचार का ऐसा दलदल पनपा है, जहां करोड़ों रुपये का काला खेल सरेआम चल रहा है। वडोदरा जिला पंचायत की अध्यक्ष ज्योत्सनाबेन वसंतभाई रबारी के पति वसंत रबारी पर अवैध रेत खनन, उगाही और करोड़ों की रॉयल्टी चोरी के जो आरोप सबूतों के साथ लगे हैं, उसने राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि जनता के वोटों पर ऐश करने वाले इन सफेदपोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रशासनिक तंत्र की औकात क्यों नहीं हो रही है?



नाकेबंदी और रॉयल्टी के बिना खड़े कर दिए रेत के पहाड़

विश्वस्त सूत्रों से मिली बेहद चौंकाने वाली जानकारी के मुताबिक, नारेश्वर से पालेज की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर बिना किसी सरकारी मंजूरी या रॉयल्टी पास के अवैध रेत का भारी स्टॉक जमा कर दिया गया है। पवित्र नर्मदा नदी का सीना चीरकर, रात-दिन जेसीबी और डंपर दौड़ाकर प्राकृतिक संपदा की अंधी लूट मचाई जा रही है। सत्ता के रसूख पर यह खनन माफिया नर्मदा नदी के अस्तित्व को संकट में डाल रहा है। सबसे बड़ा और शर्मनाक सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला सड़क पर सरेआम दिखने के बावजूद, करजण के एसडीएम शिवम बारिया, वडोदरा कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक (SP), स्थानीय तहसीलदार और खान-खनिज विभाग के अधिकारी आंखें मूंदकर क्यों बैठे हैं? करोड़ों रुपये के हफ्तों का खेल किन-किन दफ्तरों तक पहुंच रहा है कि पूरा तंत्र इस नेता के आगे घुटने टेक चुका है? क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और नेताओं के लिए लाल कालीन?

बड़ौदा डेयरी में भी दिनदहाड़े डाकाः चिलिंग सेंटर में 60 लाख का घोटाला

सत्ताधारी दल के इन पदाधिकारियों की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि वे अब गरीब पशुपालकों और दूध उत्पादकों को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं। बड़ौदा डेयरी की आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट में एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ है जिसने सहकारी क्षेत्र की नींव हिला दी है। डेयरी के सबडोल गांव में स्थित चिलिंग सेंटर में करीब 50 से 60 लाख रुपये का बड़ा वित्तीय घोटाला किए जाने की बात आधिकारिक कागजों पर साबित हो चुकी है। गरीब किसानों के पसीने की कमाई को अपने निजी स्वार्थ के लिए उड़ाने वाले इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत डेयरी प्रबंधन क्यों नहीं दिखा पा रहा है? सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक फैली यह भ्रष्ट साठगांठ वडोदरा जिले को दीमक की तरह चाट रही है।

मुख्यमंत्री तक शिकायत के बाद भी फाइलें डस्टबिन में; आखिर कब थमेगा यह खेल?

इस खुली लूट और महाभ्रष्टाचार के संबंध में खुद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तमाम पुरावे और दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत भेजी गई थी। लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री कार्यालय (ष्टस्ह्र) से भी वडोदरा के इन माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। वडोदरा का पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला या तो सत्ता के दबाव में लाचार हो चुका है या फिर इस अरबों रुपये के खेल में खुद हिस्सेदार बन बैठा है। 'महानगर मेट्रो' सरकार के इकबाल पर सीधा सवाल दागता है कि चुनावों में ईमानदारी की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के इन भ्रष्ट नेताओं पर बुलडोजर कब चलाएंगे? क्या नेताओं का यह भ्रष्टाचार ऐसे ही फलता-फूलता रहेगा या फिर जनता सड़कों पर उतरकर इस खोखली व्यवस्था की नींव हिलाने का काम करेगी?

SOG ने लोधिका के पिपलिया पाल गांव में अवैध खनन पर छापा मारा: लीज़-होल्डर पर केस दर्ज, 70.50 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

राजकोट। राजकोट रेंज के DIG निर्लिप्त राय और ग्रामीण SP विजय सिंह गुर्जर के निर्देशन में, SOG ब्रांच ने लोधिका पुलिस स्टेशन इलाके में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्ह्त ब्रांच के अधिकारी लोधिका इलाके में गश्त पर थे, तभी मिली संयुक्त सूचना के आधार पर पिपलिया पाल गांव के बाहरी इलाके में छापा मारा गया। जांच के दौरान, लीज़-होल्डर विजयपाल सिंह बलवंतसिंह चुडासमा (निवासी आंगन सिटी सोसाइटी, गांव-वावडी, राजकोट) को बिना किसी अनुमति के मोरम (तास) का अवैध खनन और परिवहन करते हुए पकड़ा गया

इस सफल छापे के दौरान, पुलिस ने कुल 70,50,000 रुपये की संपत्ति ज़ब्त की। इसमें 40 लाख रुपये की JCB मशीन, 30 लाख रुपये का डंपर और लगभग 100 टन मोरम (कीमत 50,000 रुपये) शामिल हैं। ज़ब्त किए गए सभी वाहनों और खनिजों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकोट के खान और खनिज विभाग (Mines and Minerals Department) को सौंप दिया गया है। यह सफल ऑपरेशन स्ह्त ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर F.A. पारगी, पुलिस सब-इंस्पेक्टर P.B. मिश्रा, SOG स्टाफ के A.P. कांस्टेबल रंजीतसिंह धंधल और विपुलभाई गोहिल तथा लोधिका पुलिस स्टेशन के A.H. कांस्टेबल हरपालसिंह राठौड़ द्वारा संयुक्त खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया।



कुदरती आपदा के बाद इंसानियत की मिसाल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सूरत/वडोदरा। पिछले दो दिनों से हुई भारी बारिश और उसके कारण आई भयानक बाढ़ से पूरा डायमंड सिटी सूरत पानी में डूब गया था। लोगों के घरों से लेकर व्यापारियों की दुकानों तक, हर जगह पानी ही पानी था। हालाँकि, कल बारिश रुकने के साथ ही बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन पानी उतरते ही पूरे सूरत शहर में गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य दिखाई देने लगा। अब जब महामारी फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान की ज़रूरत थी, तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मुश्किल समय में सूरत की मदद के लिए आगे आया है। सूरत शहर में फिर से जान डालने और उसे गंदगी से मुक्त करने के लिए, वडोदरा के अलग-अलग वार्डों से लगभग 200 सफाई कर्मचारियों की एक खास टीम आज सूरत के लिए रवाना हुई। इन सफाई योद्धाओं के लिए चार लग्ज़री बसों का इंतज़ाम किया गया था। कर्मचारियों के साथ-साथ, वडोदरा कॉर्पोरेशन के अलग-अलग वार्डों के बड़े अधिकारी भी उनके काम की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए खास तौर पर उनके साथ गए हैं। जब सूरत के लिए रवाना होने से पहले वडोदरा के इन सफाई कर्मचारियों से बात की गई, तो उनका उत्साह और सेवा भाव काबिले-तारीफ़ था। सफाई कर्मचारियों ने गर्व और पक्के इरादे के साथ कहा, 'हम वडोदरा को साफ रखते हैं, इसलिए सूरत भी हमारा ही हिस्सा है। जब बाढ़ की वजह से सूरत में गंदगी फैली है, तो हम वहाँ जाकर पूरी ताकत से काम करेंगे और सूरत को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाकर ही वडोदरा लौटेंगे। प्रशासन और आम जनता दोनों ही राहत की सांस ले रहे हैं कि मुसीबत के इस समय में एक शहर दूसरे शहर की मदद के लिए आगे आया है। वडोदरा के सफाई कर्मचारियों का यह जज़्बा सही मायनों में इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। आने वाले दिनों में, यह टीम सूरत के प्रभावित इलाकों में तैनात की जाएगी और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर महामारी को रोकने का काम करेगी।

SOG ने मेटोडा GIDC में बिना रॉयल्टी के रेत और बजरी के अवैध भंडारण पर छापा मारा: 'ओम कंक्रीट' से 34 लाख का सामान ज़ब्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

राजकोट। राजकोट रेंज के DIG निर्लिप्त राय और ग्रामीण SP विजय सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में, SOG शाखा ने मेटोडा GIDC पुलिस स्टेशन इलाके में वागुडल रोड पर एक बड़ी कार्रवाई की है। खान और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 'ओम कंक्रीट' यूनिट पर छापा मारा गया, जहाँ रॉयल्टी चुकाए बिना रेत और बजरी के अवैध भंडारण और परिवहन की गतिविधि पकड़ी गई। यह सफल छापा SOG पुलिस कर्मियों A.P.C. रंजीतसिंह धंधल और विपुलभाई गोहिल को मिली पक्की जानकारी के आधार पर संयुक्त रूप से मारा गया। पुलिस ने कुल 34,00,000 रुपये मूल्य का सामान ज़ब्त किया है, जिसमें 30 लाख रुपये का टाटा सिग्ना डंपर (GJ 03 BZ 7101), 2 लाख रुपये की 40 टन ब्लैक ट्रैप बजरी, 1 लाख रुपये की 100 टन रेत और 1 लाख रुपये की 50 टन बजरी शामिल है। कानूनी कार्रवाई के लिए यह सारा सामान खान और खनिज विभाग के माइन सुपरवाइज़र पूजनभाई पटेल और सर्वेयर G.V. चौहान को सौंप दिया गया है। इस अवैध गतिविधि में शामिल 'ओम कंक्रीट' यूनिट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। यह सफल ऑपरेशन SOG के P.Ins. F.A. पारगी के आदेश पर P.S. Ins. G.J. झाला, P.S. Ins. P.B. मिश्रा और उनके स्टाफ द्वारा चलाया गया।



अखिल भारत हिन्दू क्रान्ति सेना ने अवनीश श्रीवास्तव को बनाया राष्ट्रीय संयोजक



महानगर मेट्रो ब्यूरो

प्रयागराज। अखिल भारत हिन्दू क्रान्ति सेना के संगठनात्मक विस्तार एवं राष्ट्रव्यापी गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनन्द सोनी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री पवन माकन ने प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) निवासी श्री अवनीश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय संयोजक पद पर नियुक्त किया है। संगठन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में बताया गया कि श्री अवनीश श्रीवास्तव लंबे समय से संगठन की विचारधारा एवं सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी कार्यशैली, संगठन के प्रति समर्पण तथा विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक समन्वय स्थापित करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि श्री अवनीश श्रीवास्तव इससे पूर्व अखिल भारत हिन्दू क्रान्ति सेना में राष्ट्रीय सह संयोजक के पद का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनन्द सोनी ने कहा कि संगठन लगातार देशभर में अपने कार्यों का विस्तार कर रहा है

नवीन कडवाल तालुका पंचायत की विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव

महानगर मेट्रो ब्यूरो

तालुका। नवीन कडवाल तालुका पंचायत में विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर तालुका पंचायत के सदस्य, नेता, कार्यकर्ता और शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। सामाजिक न्याय समिति की अध्यक्ष सुमीबेन दिव्येशभाई सह-चयनित सदस्य हरिजन अशोकभाई अरविंदभाई. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने उन पर भरोसा जताने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और तालुका के सर्वांगीण विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि नई टीम के नेतृत्व में तालुका में विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा आम नागरिकों की समस्याओं के समय पर और प्रभावी समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। अंत में, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गईं। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी जीत पर बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं... इरफान मकरानी कडवाल

पुलिस कॉन्स्टेबल अमीनहुसैन को लिंचिंग के मामले को सुलझाने के लिए 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया



महानगर मेट्रो ब्यूरो

कडी/मेहसाणा। ACB (एंटी-करप्शन ब्यूरो) ने मेहसाणा जिले में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले के कडी पुलिस स्टेशन में तैनात एक भ्रष्ट पुलिस कॉन्स्टेबल को मेहसाणा ACB ने लंग्नाज पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले को सुलझाने के बहाने 80,000 की भारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ACB ने कॉन्स्टेबल अमीनहुसैन मंजूरहुसैन को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, कडी पुलिस स्टेशन के कॉन्स्टेबल अमीनहुसैन मंजूरहुसैन ने लंग्नाज पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले को सुलझाने और शिकायतकर्ता की मदद करने के बदले ?80,000 की रिश्वत मांगी थी। हालांकि, सतर्क नागरिक रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मेहसाणा ACB कार्यालय से संपर्क किया और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, ACB टीम ने पहले से बनी योजना के अनुसार कडी इलाके में रिश्वत का जाल बिछाया। इस बीच, जब कडी पुलिस स्टेशन का कॉन्स्टेबल अमीनहुसैन मंजूरहुसैन शिकायतकर्ता से ?80,000 की नकद रिश्वत लेने पहुंचा, तो छिपी हुई ACB टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB ने रिश्वत की रकम जब्त कर ली है और आरोपी कॉन्स्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। कानून लागू करने वाले अधिकारी द्वारा इस तरह रिश्वत लेने की घटना ने पुलिस बल के भीतर हलचल मचा दी है, जबकि मेहसाणा ACB के इस सफल ऑपरेशन से अन्य भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

संक्षिप्त न्यूज

अहमदाबाद में 188 आधुनिक सरकारी आवासों का 12 जुलाई को उद्घाटन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। 60.68 करोड़ की लागत से बने 188 आधुनिक सरकारी आवासों का 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ई-उद्घाटन करेंगे। चार टावरों में बने इन आवासों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका आवंटन क्लास-1, क्लास-2 और क्लास-3 के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को किया जाएगा। परियोजना से कर्मचारियों को बेहतर आवास और कार्यस्थल के करीब रहने का लाभ मिलेगा।

विधवा सहायता प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत, कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पाटन। चनास्मा मामलतदार कार्यालय में एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश परमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर विधवा सहायता प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

149वीं रथ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट वेदनशील इलाकों में पैदल गश्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, एसओजी और स्थानीय पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त फुट पेट्रोलिंग की। रूट का निरीक्षण करने के साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

149वीं रथ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट वेदनशील इलाकों में पैदल गश्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। बढ़ती फीस, डोनेशन और कोचिंग संस्कृति को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में शिक्षा के व्यवसायीकरण से मध्यम और गरीब परिवारों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा प्रमुखता से सामने रखा गया है। साथ ही फीस नियंत्रण, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि बेहतर नागरिक तैयार करना होना चाहिए।

इंस्टाग्राम विवाद में युवक की हत्या, दो घायल

महानगर मेट्रो ब्यूरो



गुजरात। बोटाद में इंस्टाग्राम फ्रेंड रिक्वेस्ट को लेकर हुए विवाद में 23 वर्षीय हरपाल खाचर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हमले में दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

डभोई के कुकड़ गांव में प्रशासन की भारी लापरवाही: दिशा और मोड़ बताने वाले साइन बोर्ड एक महीने से ज़मीन पर पड़े हैं

सड़क और भवन विभाग शायद किसी बड़े हादसे और किसी बेगुनाह की मौत का इंतज़ार कर रहा है

महानगर मेट्रो ब्यूरो

डभोई। डभोई तालुका के कुकड़ गांव की मुख्य सड़कों पर सरकारी प्रशासन की ऐसी भारी लापरवाही और सुस्ती सामने आई है, जो किसी भी समय किसी बेगुनाह वाहन चालक की जान ले सकती है। कुकड़ गांव के पास बहुत ज़रूरी मोड़ों (curves) और गांव का नाम बताने वाले मुख्य साइन बोर्ड पिछले एक महीने से टूटे हुए और ज़मीन पर पड़े हैं। इस गंभीर मामले को एक महीना बीत जाने के बाद भी, सड़क और भवन विभाग (रोड डिपार्टमेंट) के अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है! किसी भी भ्रष्ट या सुस्त अधिकारी ने सड़क किनारे धूल फांक रहे इस बोर्ड को दोबारा लगाने की ज़हमत नहीं उठाई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों में सिस्टम के खिलाफ़ काफी गुस्सा है। दिन के समय तो सड़क का रास्ता समझ आ जाता है, लेकिन रात के घने अंधेरे में इस सड़क से गुज़रने वाले अनजान वाहन चालकों के लिए स्थिति बेहद गंभीर और खतरनाक हो जाती है। सड़क पर खतरनाक मोड़ों को बताने वाले साइन बोर्ड न होने के कारण, रात में तेज़ी से आने वाले वाहन चालकों को पता नहीं चलता कि मोड़ कहाँ है। हेडलाइट की रोशनी में भी साइन बोर्ड दिखाई न देने के कारण, यहाँ गंभीर दुर्घटना की पूरी संभावना बनी रहती है। मुश्किल यह भी है कि कुकड़ गांव का नाम बताने वाला मुख्य बोर्ड भी ज़मीन पर पड़ा है, इसलिए बाहर से आने वाले यात्रियों या रिश्तेदारों को यह पता नहीं चल पाता कि वे किस गांव में आए हैं। नतीजतन, अनजान लोग रात में सड़कों पर भटकते रहते हैं और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की इस अनदेखी और लापरवाही के खिलाफ़ अब स्थानीय लोगों में तीखी नाराज़गी और गुस्सा है। ग्रामीण पूछ रहे हैं, 'क्या सरकार से



लाखों रुपये की सैलरी पाने वाले ज़िम्मेदार अधिकारी कभी अपने AC दफ़्तरों से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हैं? ' अगर ये अधिकारी सच में कागज़ों पर दिखाए गए अनुसार फ़ील्ड विज़िट कर रहे हैं, तो उन्हें सड़क के किनारे एक महीने से कचरे की तरह पड़े ये बोर्ड क्यों नहीं दिखते? क्या ये बाबू अंधे हैं या जान-बूझकर सोए हुए हैं? प्रशासन की यह घोर लापरवाही साफ़ करती है कि उन्हें जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। क्या सड़क और आवास विभाग इस सड़क पर किसी भयानक हादसे और किसी नागरिक की मौत का इंतज़ार कर रहा है? स्थानीय लोगों ने अब चेतावनी दी है कि अगर इस बोर्ड को तुरंत दोबारा नहीं लगाया गया, तो सबसे ऊँचे स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा।

डभोई में भ्रष्टाचार या प्रशासन की भारी लापरवाही? स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी रोड पर सिर्फ़ 15 दिन पहले लगाई गई लाखों की कीमत वाली जालियां गायब हो गई हैं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

डभोई। शिनोर चौकड़ी से नादोदी भागोल और वहां से तीर्थ स्थल एकता नगर (केवड़िया) को जोड़ने वाले अहम स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी हाईवे पर हाल ही में लगाई गई मज़बूत लोहे की सुरक्षा रेलिंग (जालियां) के गायब होने से बड़ी बहस छिड़ गई है। हैरानी की बात है कि इस काम को पूरा हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि सड़क के बीच से कीमती लोहे की जालियां गायब हो गईं, जिससे सरकारी सिस्टम के कामकाज और सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन जालियों को लगाने का मुख्य मकसद सड़क सुरक्षा था। इस व्यस्त हाईवे से हर दिन हज़ारों गाड़ियां गुज़रती हैं। आवारा मवेशियों या दूसरे जानवरों के अचानक सड़क के बीच आने और उससे होने वाले गंभीर हादसों को रोकने के नेक इरादे से सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके ये डिवाइडर सुरक्षा जालियां लगाई थीं, लेकिन सिर्फ़ 15 दिनों में ही रेलिंग गायब हो गई, जिससे वाहन चालकों की सुरक्षा फिर से खतरे में पड़ गई है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यह है कि जहां से ये रेलिंग गायब हुई हैं, उसके बहुत पास ही सड़क और भवन विभाग का दफ़्तर है। सरकारी संपत्ति ठीक उनकी नाक के नीचे से गायब हो रही है, फिर भी सिस्टम गहरी नींद में सोया हुआ लगता है। क्या ये जालियां किसी तस्करी करने वाले गिरोह ने चुराई हैं या किसी हादसे में ये टूट गई और दफ़्तर में जमा कर दी गई? अगर कोई हादसा हुआ था, तो ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह एक बड़ा रहस्य बन गया है। प्रशासन के खिलाफ़ स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों के बीच चर्चा है कि या तो इन जालियों को लगाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ था जिससे इन्हें आसानी से हटा दिया गया, या फिर प्रशासन की शह पर ये चोरियां हो रही हैं। यह समझना आसान है कि ज़िम्मेदार अधिकारी क्यों चुप बैठे हैं, जबकि कुछ ही दिनों में दिन-दहाड़े सरकारी संपत्ति गायब हो रही है। स्थानीय नागरिक अब इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।





डुबोने की कोई पक्की साज़िश थी? क्या भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों की वजह से सूरत के लोगों को बिना इंजन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सूरत/वराछा। सूरत में आई भयानक बाढ़ और प्रशासन की लापरवाही के कारण वराछा के लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। बाढ़ के दौरान वराछा और उसके आस-पास के इलाकों के पानी में डूबने का मंज़र देखकर, अब आम नागरिक भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या भ्रष्ट अधिकारियों ने वराछा के लोगों को डुबोने के लिए कोई पक्की साज़िश रची थी? इस आपदा के समय, नगर पालिका और प्रशासन के पापों का घड़ा एक-एक करके फूट रहा है। जब बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों के लिए करोड़ों की लागत से बनी नावें उतारी जानी थीं, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई जिसने सूरत के लोगों को हैरान कर दिया। आपदा के समय लोगों की जान बचाने के लिए जिन नावों को चलना था, उनमें से महंगे इंजन ही गायब थे! जनता अब तीखा सवाल पूछ रही है कि क्या ये बिना इंजन वाली नावें सिर्फ़ शोरूम में सजाने और कागज़ों पर दिखाने के लिए मंगवाई गई थीं? हर साल मॉनसून से पहले की तैयारियों और आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं। आपदा के समय लोगों को मदद मिल सके, इसके लिए आधुनिक नावें और उपकरण खरीदे जाते हैं। लेकिन वराछा के लोग आज पूछ रहे हैं कि बिना इंजन वाली नावें बाढ़ की तेज़ लहरों में लोगों की जान कैसे बचा सकती हैं? ये महंगे और कीमती इंजन कहाँ गए? किस भ्रष्ट अधिकारी या ठेकेदार ने मिलीभगत करके ये इंजन बेचे और उनका पैसा डकारा? इस पूरे घोटाले की उच्च-स्तरीय जाँच ज़रूरी है। अधिकारियों की एयर-कंडीशंड केबिन में प्लानिंग, और लोग सड़कों पर बेबस जब आम लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा था और लाखों का नुकसान हो रहा था, तब ये भ्रष्ट अधिकारी अपने एयर-कंडीशंड केबिन में बैठकर कागज़ों पर सब कुछ 'ठीक-ठाक' दिखा रहे थे। प्रशासन की भारी लापरवाही के कारण वराछा जैसा चहल-पहल वाला और जागरूक इलाका कई दिनों तक बंद रहा। नावें होने के बावजूद, इंजन न होने की वजह से बचाव कार्य रुका रहा। इससे साबित होता है कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ़ छोटा-मोटा नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। अब वराछा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं: वे कौन राक्षस हैं जो जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई नावों के इंजन चुरा लेते हैं? आने वाले दिनों में सूरत में प्रशासन के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।

भीनमाल में कल लगेगा 139 वां निःशुल्क नेत्र जांच व मोतियाबिंद शिविर, आबूरोड के विशेषज्ञ करेंगे इलाज

महानगर मेट्रो ब्यूरो





भीनमाल (मुकेश सोलंकी)। स्थानीय इंद्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्माकुमारी राजयोग केंद्र पर रविवार, 12 जुलाई को 139वें विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला अंधता निवारण समिति जालोर और ग्लोबल नेत्र संस्थान आबूरोड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। ब्रह्माकुमारी केंद्र की बी. के. गीता बहन ने बताया कि एक गुप्त दानदाता के विशेष आर्थिक सहयोग से यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें ग्लोबल नेत्र संस्थान आबूरोड के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी। ब्रह्माकुमारी केंद्र की बी. के. गीता बहन ने बताया कि एक गुप्त दानदाता के विशेष आर्थिक सहयोग से यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें ग्लोबल नेत्र संस्थान आबूरोड के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी। जांच में मोतियाबिंद पाए जाने वाले मरीजों के ऑपरेशन ग्लोबल नेत्र संस्थान के बेस अस्पताल में निःशुल्क किए जाएंगे। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां और परामर्श भी दिया जाएगा। बी. के. गीता बहन ने असहाय व जरूरतमंद लोगों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। मरीज अपने साथ आधार कार्ड और पुरानी जांच पर्चियां जरूर लाएं।

कागडापीठ और कालूपुर में नौकरों द्वारा की गई चोरी का मामला सुलझा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। कागडापीठ पुलिस को शहर के व्यापारिक केंद्र माने जाने वाले कागडापीठ और कालूपुर इलाकों की कपड़ा दुकानों में नौकरों द्वारा की गई बड़ी चोरी की गुत्थी सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। मामले की गहन जांच के बाद, पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 4 लाख रुपये का कपड़ा ज़ब्त किया है। हालांकि, चोरी को अंजाम देने वाले दुकान के 5 मुख्य आरोपी नौकर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कपड़ा दुकानों से सामान गायब होने के संबंध में कागडापीठ और कालूपुर पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। गिरफ्तार आरोपियों से 4 लाख रुपये का चोरी हुआ कपड़ा भी बरामद किया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ, पुलिस ने कागडापीठ और कालूपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में दर्ज कुल दो बड़े अपराधों को सुलझा लिया है। फिलहाल, कागडापीठ पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, जबकि सामान चुराकर भागने वाले पांच कर्मचारियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं।

इंदिरा नगरी में छापेमारी के दौरान ?5.57 लाख की विदेशी शराब के साथ कुख्यात शराब तस्कर अर्जुन कगसिया गिरफ्तार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नडियाद। खेड़ा जिले में शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत नडियाद वेस्ट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने नडियाद के इंदिरा नगरी इलाके में छापेमारी की और इलाके के कुख्यात शराब तस्कर अर्जुन कगसिया को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने मौके से कुल 5.57 लाख की अवैध शराब जब्त की है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, जब नडियाद वेस्ट पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तो उन्हें पक्की और सटीक सूचना मिली कि इंदिरा नगरी में रहने वाला कुख्यात शराब तस्कर अर्जुन कगसिया भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर, वेस्ट पुलिस टीम ने निगरानी रखी और इंदिरा नगरी में एक खास जगह पर अचानक छापेमारी की। पुलिस की इस छापेमारी के दौरान घर में अलग-अलग ब्रांड की भारतीय निर्मित विदेशी शराब के बॉक्स और बोतलें मिलीं। पुलिस ने इस शराब की कुल कीमत 5,57,000 आंकी है। पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है और शराब तस्कर अर्जुन कगसिया को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट पुलिस ने इस मामले में प्रोहिबिशन एक्ट (शराबबंदी कानून) के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है .

उनावा से केमिकल वाले रंग से मिलावटी होने के शक में 26 टन सौंफ ज़ब्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मेहसाणा/ऊंझा। गुजरात सरकार राज्य के नागरिकों की सेहत को लेकर मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के नेतृत्व में, खाद्य एवं औषधि विभाग ने 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के साथ एक सख्त अभियान शुरू किया है। इसी के तहत, मेहसाणा जिले के ऊंझा के पास उनावा से केमिकल वाले रंग से मिलावटी होने के शक में 26 टन से ज़्यादा सौंफ (कीमत लगभग 19.6 लाख रुपये) ज़ब्त की गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने बताया कि खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरण के फ्लाइंग स्क्वाड ने गुप्त सूचना के आधार पर उनावा में दो जगहों पर अचानक छापेमारी की। इसमें अवैध गतिविधियों में शामिल फर्म पकड़ी गईं। एजेंसी की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आम सौंफ में केमिकल-आधारित खाने-अयोग्य रंग मिलाए जा रहे थे ताकि वह ग्राहकों को बहुत ज़्यादा हरी और आकर्षक दिखे। यह केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान यह भी पता चला कि इन फर्मों के पास खाद्य पदार्थों के उत्पादन या भंडारण के लिए ज़रूरी फूड सेफ्टी लाइसेंस (FSSAI लाइसेंस) नहीं था। सौंफ के तीन कानूनी सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।



देश में 94,000 सरकारी स्कूल 'हमेशा के लिए बंद' हो गए हैं: क्या पिछले 10 सालों का यह आंकड़ा सरकार की 'बड़ी कामयाबी' है

महानगर मेट्रो ब्यूरो



गांधीनगर/नई दिल्ली। 'देश में 94,000 स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गए हैं... सोचिए!' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर PMO इंडिया, CMO गुजरात और रिवाबा जडेजा जैसे बड़े अकाउंट्स को टैग करके वायरल हुए इस एक लाइन के मैसेज ने देश की राजनीति और शिक्षा जगत में भारी हलचल मचा दी है। जब विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच पिछले 10 सालों में देश भर में हजारों सरकारी स्कूलों के बंद होने के आंकड़े इस तरह सामने आते हैं, तो यह सिस्टम की 'कामयाबी' पर एक बहुत बड़ा और तीखा तंज बन जाता है। सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स और सवाल उठाने वाले लोग पूछ रहे हैं कि स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के ऊंचे नारों के बीच देश के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल एक-एक करके क्यों बंद हो रहे हैं? पिछले दशक में 94,000 स्कूलों का बंद होना या दूसरे स्कूलों में उनका विलय होना कोई मामूली बात नहीं है। यह आंकड़ा दिखाता है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अच्छी शिक्षा का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों और रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अक्सर कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों में 'मिलाने' (विलय करने) का तर्क देती है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक आसानी और संसाधनों के सही इस्तेमाल के नाम पर की जाती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जब किसी गांव का एकमात्र सरकारी स्कूल बंद हो जाता है, तो गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नतीजतन, ड्रॉप-आउट रेश्यो (बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर), खासकर लड़कियों के मामले में, बढ़ जाता है। एक तरफ, प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस आम माता-पिता की कमर तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ, इस तरह सरकारी स्कूलों का गायब होना चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन जानकारियों ने देश और राज्य की मॉनिटरिंग सेल (CMO और PMO) को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है।

कमलम में 'नो-मोबाइल ज़ोन': BJP की हाई-प्रोफाइल बैठकों से मोबाइल फोन बाहर! नेताओं पर अविश्वास या गोपनीयता बनाए रखने की नई चाल?

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गांधीनगर। गुजरात BJP के राज्य मुख्यालय 'श्री कमलम' से एक खबर सामने आ रही है, जिसने पार्टी के अंदरूनी हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। ऐसा लगता है कि अनुशासन और हाई-टेक डिजिटल प्रचार का दम भरने वाली BJP का अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि अब महत्वपूर्ण बैठकों में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह रोक (नो एंट्री) लगा दी गई है! इस फैसले के बाद गांधीनगर के राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी और अंदरूनी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कमलम में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों में सभी मंत्रियों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के मोबाइल फोन मीटिंग हॉल के बाहर जमा करवा लिए गए। पार्टी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतना सख्त फैसला देखा गया है। अब तक, जो नेता अपनी जेब या हाथ में iPhone रखते थे और गेम खेलते थे, उन्हें बैठक से पहले अपने कीमती मोबाइल फोन बाहर टेबल पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कड़ा फैसला क्यों लिया गया? अंदर क्या पक रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों और कमलम के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और लगातार हो रही लीक की घटनाएं इस फैसले के लिए जिम्मेदार हैं। डिजिटल जासूसी और बगावत के इस डर से बचने के लिए, पार्टी ने अब 'ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी' जैसा कड़ा कदम उठाया है।

सूरत में बाढ़ का असली खेल: कुमार कनानी का 'इंसान की बनाई आपदा' वाला कबूलनामा, व्यापारी के 'स्टील के कीड़े' और हर्षभाई की 'चाय पर चर्चा' का जादू!

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सूरत। भयानक बाढ़ के बाद, व्यापारियों को चाहे वे टेक्सटाइल मार्केट के हों या दूसरे सेक्टर के अरबों रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा। शुरू में, सूरत के बेचारे भोले-भाले लोग इसे 'कुदरती आपदा' मानकर अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। लेकिन, बीजेपी विधायक कुमार कनानी के एक बयान ने पूरा खेल ही पलट दिया। कनानी के बयान के बाद, पूरे सूरत को एहसास हुआ कि यह कोई कुदरती आपदा नहीं थी। सूरत के लोग कुदरती आपदाओं का सामना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह 'इंसान की बनाई आपदा' थी जो भ्रष्टाचार की गंदगी से निकली थी, जिसमें पूरा सूरत डूब गया था। जब नुकसान की वजह से व्यापारियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, तो पोदार आर्केड के एक व्यापारी ने हाथ में 'स्टील के कीड़े' (लोहे की छड़ें) लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया। उनका निशाना कोई और नहीं, बल्कि वे भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने सूरत को डुबो दिया था! जैसे ही गुस्से और आक्रोश से भरा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दूसरे व्यापारियों को भी हिम्मत मिली। हर तरफ से कॉरपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ वीडियो की बाढ़ आ गई। जनता का गुस्सा इस कदर भड़का दूसरी ओर, इस आपदा में पुलिस का काम इतना सराहनीय था कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और खुद सूरत के लोगों ने इसकी तारीफ की।

आज का राशिफल

11 जुलाई 2026, शनिवार

मेष	आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
वृषभ	नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
मिथुन	रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।
कर्क	नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खर्च नियंत्रित रखें।
सिंह	आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।
कन्या	मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा।
तुला	दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। कारोबार में लाभ होगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
वृश्चिक	कार्याओं में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।
धनु	भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी।
मकर	निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
कुंभ	नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा।
मीन	आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंका



पवन माकन
ग्रुप एडिटर, महानगर मेट्रो

नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूंक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खतरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा।

हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा



अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थायी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है।

देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या अध्ययन अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत जनसंख्या में हो रहे अस्वाभाविक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा, उनके कारणों की पहचान होगी और भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्वाभाविक कारणों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर कठोरता के साथ नियंत्रण किया जाएगा। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक तत्काल पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर भी अभूतपूर्व निवेश कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर निवेश में चार सौ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़कों, संचार व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा के सोलह सौ दस किलोमीटर लंबे हिस्से पर 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य केवल घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि छद्म युद्ध, अवैध हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित अन्य गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

साथ ही मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचानकर उन्हें रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साइबर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तुत यह नई रणनीति केवल सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सामरिक शक्ति और भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने वाला व्यापक अभियान बनकर उभर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह स्वयं भी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों के साथ संवाद स्थापित किया, नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया, भारत-पाक सीमा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र जाकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और महिला जवानों के लिए नई बैरकों का उद्घाटन किया। स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र, मजबूत समन्वय और प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे सीमा सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

संपादकीय

सरकारी से मोहभंग

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। ह्यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लसह्न के अनुसार शुरूआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023-24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025-26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादतर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है। दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र-शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है।

चिंतन-मनन

भगवान की विचारणाएं

जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं और पैदा हुआ हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान द्वारा सोचना, विचारना, बोलना, भावनाएं आदि अमानतें मनुष्य को इसलिए नहीं दी गई हैं कि उनके द्वारा वह सुख-सुविधाएं या विलासिता के साधन जुटा अपना अहंकार पूरा करे बल्कि इसलिए दी गयी हैं ताकि इनके माध्यम से वह विश्व को अधिक सुन्दर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न कर।

बैंक के खजांची के पास धन इसलिए रखा रहता है ताकि सरकारी प्रयोजनों के लिए इस पैसे को खर्च कर। खजाने में रखे लाखों रुपये खजांची कैसे खर्च कर सकता है।अपने लिए उसे उतना ही इस्तेमाल करने का हक है, जितना उसे वेतन मिलता है। पुलिस और फौज का कमांडर है, उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं, उसी से काम चलाना चाहिए। बाकी बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति उसे बंदूक चलाने के लिए मिली है, उसे सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने उसको सौंपा है।

हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ विभूतियां, अक्ल और विशेषताएं हैं, वे व्यक्तिगत ऐय्याशी सुविधा और शौक-मौज के लिए नहीं हैं। व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं है। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है- निरूस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्यार किया। मनुष्य को उस तरह का मस्तिष्क दिया है, जितना कीमती कम्प्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। मनुष्य की आंखें, कान, नाक, वाणी एक से एक चीजें हैं, जिनकी रुपयों में कीमत नहीं आंकी जाती है। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है, जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्योछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य जिस भगवान ने बनाया है, उसकी यह आकांक्षा जरूर रही है कि दुनिया को समुन्नत और सुखी बनाने में यह प्राणी मेरे सहायक के रूप में काम करेगा और मेरी सृष्टि को समुन्नत रखेगा। मानव जीवन की विशेषताओं और भगवान द्वारा विशेष विभूतियां मनुष्य को देने का एक और उद्देश्य है। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं और पैदा हुआ हूं तो मुझे क्या करना चाहिएट तो समझना चाहिए कि इस आदमी का नाम मनुष्य है, इसके भीतर मनुष्यता का उदय हुआ और इसके अंदर भगवान की विचारणाएं उदित हो गयीं।

विकसित भारत की राह में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न



ललित गर्ग

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- 'युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए।' यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है।

भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अतः सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से बढ़कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दशार्ती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो विकसित भारत का लक्ष्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जनगणना और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस नीति में संशोधन भी किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, इसलिए यहां समाधान कठोर दमनात्मक उपायों के बजाय समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, परिवार नियोजन, जन-जागरूकता और कानून के निष्पक्ष अनुपालन में निहित है। जनसंख्या के प्रश्न को जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के हित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम भी इसी दिशा में संकेत करती है कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिलेंगे, तो वे स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनकर संतुलित परिवार और सतत विकास की दिशा में योगदान देंगे। भारत की लगभग आधी आबादी युवा है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश तभी राष्ट्र की शक्ति बनेगा, जब यह शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। अन्यथा यही विशाल युवा आबादी बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक व्यापक, वैज्ञानिक और सर्वसम्मत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसी नीति में समानता, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी किसी भी चर्चा में सामाजिक सौहार्द, तथ्यपरक विश्लेषण और जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या विभाजनकारी दृष्टिकोण समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे सकता है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, मानव पूंजी में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, प्रभावी सीमा प्रबंधन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति-इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। यदि भारत समय रहते जनसंख्या संतुलन, मानव विकास और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का लक्ष्य अधिक यथार्थ रूप में साकार हो सकेगा।

समान नागरिक संहिताः कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात?



दिलीप कुमार पाठक

भारत की राजनीति में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है, जो जब भी सामने आता है, अपने साथ बहसों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इसे लागू किए जाने के बाद, अब देश के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्रों में ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया जाए। लेकिन क्या देश के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में से एक में इसे लागू करना इतना सीधा रास्ता है? या फिर इस कदम की टाइमिंग के पीछे चुनावी समीकरणों की कोई गहरी बिसात बिछी है?

जब हम सरकार के इस फैसले को बारीकी से देखते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को निष्पक्षता से तौलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज नीति निदेशक तत्वों के तहत एक राष्ट्र, एक कानून के सपने को सच करने की दिशा में एक साहसिक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा और सदियों पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। इस समिति की कमान जस्टिस रंजना देसाई को सौंपना प्रशासनिक रूप से एक सोची-समझी रणनीति दिखती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले उत्तराखंड के कानून का मसौदा तैयार किया था। उनके इस तकनीकी अनुभव का लाभ महाराष्ट्र सरकार उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में शाह बानो और सरला मुद्गल जैसे ऐतिहासिक मामलों में देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया है, जिससे इस विचार को संवैधानिक मजबूती मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर और वास्तविक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसी सीमित आबादी वाले राज्य और महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं, प्रथाएं और सामाजिक नियम हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल अल्पसंख्यक समुदाय और अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों का एक बेहद पेचीदा ताना-बाना है। इतने बड़े और विविधता से भरे राज्य में बिना किसी व्यापक सामाजिक संवाद के, केवल छह महीने के भीतर एकतरफा मसौदा तैयार कर लेना जमीनी सच्चाइयों से आंखें मूंदने जैसा हो सकता है।

भारत का संविधान जहां एक तरफ समानता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी कानूनविद के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। एक और बड़ा सवाल इस समिति की बनावट पर भी उठ रहा है। सात सदस्यों की इस समिति में पूर्व जजों, पूर्व मुख्य सचिव और संवैधानिक विशेषज्ञों को तो जगह मिली है, लेकिन अल्पसंख्यक या आदिवासी समुदायों के जमीनी प्रतिनिधियों की कमी साफ खलती है। जब आप समाज के हर वर्ग के निजी जीवन को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा कानून बनाने जा रहे हों, तो उस चर्चा की मेज पर सभी पक्षों की मौजूदगी न होना कानून की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के हर तबके को अपना सा लगे, न कि किसी पर थोपा हुआ महसूस हो। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की टाइमिंग पर भी लगातार उंगली उठा रहे हैं। यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश या राज्य में जब भी कोई बड़ा चुनाव नजदीक आता है या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले होते हैं, तभी समान नागरिक संहिता जैसे भावनात्मक मुद्दों को तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जाता है? अगर मंशा सचमुच केवल कानूनी और सामाजिक सुधार की है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जन-सुनवाई क्यों नहीं की जाती? सभी हितधारकों, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से खुलकर चर्चा करने में आखिर क्या हिचक है? समान नागरिक संहिता अपने आप में एक प्रगतिशील और आधुनिक विचार हो सकती है, बशर्ते उसे सुधार की सच्ची नीयत से लाया जाए, न कि किसी राजनीतिक लाभ या ध्रुवीकरण के लिए। भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में कोई भी नागरिक कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। यदि महाराष्ट्र सरकार वाकई इस दिशा में कोई सार्थक और ऐतिहासिक बदलाव करना चाहती है, तो उसे जल्दबाजी छोड़कर इस कानून को सर्वसम्मति, पारदर्शिता और बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा, यह कदम भी एक वास्तविक सामाजिक सुधार बनने के बजाय केवल एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा।

(लेखक पत्रकार हैं)

दूल्हे के भाई ने खींच दिया दुल्हन का पल्लू, मंडप में चले लात-घूंसे, फेरों से पहले जाना पड़ा थाने

महानगर मेट्रो ब्यूरो

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में राजकुमार की बेटी नन्ही और सीतापुर के दिनेश के विवाह समारोह के दौरान फेरों के समय एक अनोखा विवाद हो गया. अंतिम फेरों के वक्त दूल्हे के छोटे भाई मुकेश ने मजाक में दुल्हन का पल्लू खींच दिया. इस बात पर दुल्हन के चाचा पिंकू के आपत्ति जताने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. नशे में धुत कुछ लोगों के कारण यह मामूली विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन का चचेरा भाई घायल हो गए. इसके बाद शादी रोककर दोनों पक्षों को अतरौली थाने जाना पड़ा.



मजाक पड़ा भारी, मंडप में चले लात-घूंसे

फेरों के पवित्र माहौल में हुई इस हरकत ने शादी की खुशियों को पल भर में हंगामे में बदल दिया. दूल्हे के भाई की इस अजीब मजाक वाली हरकत पर जब वधू पक्ष ने टोका, तो दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए. इस मारपीट में दूल्हे दिनेश के सिर में चोट आई, जबकि दुल्हन का चचेरा भाई रामू भी घायल हो गया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आधी रात को ही शादी की रस्में रोक दी गईं. गुरुवार दोपहर को यह पूरा मामला अतरौली पुलिस थाने पहुंचा. वहां गांव के प्रधान पति रामलखन की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत हुई. आपसी सहमति से दोनों पक्षों में समझौता कराया गया, जिसके तहत घायलों के इलाज के लिए 4,500 रुपये दिए गए. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के बाद कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

अधूरी भांवरें हुईं पूरी, शाम को हुई विदाई

थाने से समझौता होने के बाद दोनों पक्ष वापस गांव लौटे. गुरुवार शाम को मंडप में बची हुई दो भांवरें पूरी कराई गईं. इसके बाद दूल्हे दिनेश ने दुल्हन नन्ही की मांग में सिंदूर भरा और विवाह की शेष रस्में पूरी कीं. विवाह संपन्न होने के बाद परिजनों ने खुशी-खुशी दुल्हन को ससुराल के लिए विदा किया.

अयोध्या के भदरसा का नाम बदला, अब 'भरत नगर' से होगी नई पहचान



महानगर मेट्रो ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर 'भरत नगर' करने का ऐलान किया. उन्होंने बिकापुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान यह घोषणा की. इसके साथ ही नवगठित खिलौनी-सुचितागंज नगर पंचायत का नाम बदलकर 'मां ज्वाला जी नगर पंचायत' रखने की भी घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि भदरसा अब भरत नगर के नाम से जाना जाएगा. साथ ही, भरत कुंड से जुड़े क्षेत्र की पहचान भी भरत नगर के रूप में विकसित की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह फैसला भगवान श्रीराम के छोटे भाई भरत के त्याग, समर्पण और आदर्शों को सम्मान देने के लिए लिया गया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तब भरत ने अयोध्या का सिंहासन स्वीकार नहीं किया. उन्होंने श्रीराम की खड़ाऊं को राजसिंहासन पर स्थापित कर स्वयं भरत कुंड में रहकर राज्य का संचालन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में भरत जैसा भाई मिलना कठिन है और उनका जीवन त्याग और मर्यादा की मिसाल है.

भदरसा का नाम बदलकर भरत नगर किया गया

मुख्यमंत्री ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भदरसा में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों का व्यवहार जनता ने देखा है, जो उनके वास्तविक चरित्र को दर्शाता है. इसी संदर्भ में उन्होंने भदरसा का नाम बदलकर भरत नगर करने की घोषणा की. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पूरे देश के लिए प्रेरणा है. सरकार भरत नगर को एक विकसित नगर पंचायत के रूप में आगे बढ़ाएगी और यहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों में कई शहरों और कस्बों के नाम बदल चुकी है. हाल ही में शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर 'भगवान परशुराम पुरी' करने की घोषणा की गई थी. इससे पहले कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम 'पावागढ़' करने का ऐलान हुआ था. वहीं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया जा चुका है.



पेट का ऑपरेशन और लगे थे टांके, फिर भी गुना में मुनीम की आँखों में स्प्रे डाल लूट ले गया लाखो रुपये, पुलिस ने शातिर लुटेरों को ऐसे दबोचा

गुना में धनिया व्यापारी के मुनीम से हुई 17 लाख की लूट का एसपी हितिका वासल की टीम ने महज 18 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने बरामद नोटों की गड्डियों से गुना पुलिस का साइन बनाया। जानें कैसे घर के किरायेदार ने ही कराई यह बड़ी लूट

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गुना। शहर के निचला बाजार रपटा क्षेत्र में धनिया व्यापारी के मुनीम से हुई 17 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट के मामले में गुना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल के निर्देशन में गठित 6 विशेष टीमों ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से महज 18 घंटे के भीतर अंधी लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य लुटेरों, उन्हें कार से भगाने वाले मददगार और मुनीम की सटीक मुखबिरी करने वाले मास्टरमाइंड सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट की राशि में से 16 लाख 77 हजार 100 रुपये की भारी-भरकम नकदी और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद कर ली गई है। इस पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा एसपी हितिका वासल ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प और अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां पुलिस टीम ने



आरोपियों से बरामद की गई नोटों की गड्डियों को टेबल पर बेहद करीने से सजाकर बकायदा एक बड़ा GUNA POLICE का साइन बनाया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य लुटेरा राघव शर्मा है, जिसने पेट का बड़ा ऑपरेशन होने और टांके लगे होने के बावजूद इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में... राघव शर्मा (26 वर्ष) - निवासी आरोन, गुना (मुख्य लुटेरा) राहुल जाटव (25 वर्ष) - निवासी आरोन (कार से लुटेरों को भगाने वाला मददगार) विजय उर्फ संजीव यादव (21 वर्ष) -

निवासी अशोकनगर (मुख्य मुखबिर) पूछताछ में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुखबिरी को लेकर हुआ। पीड़ित मुनीम वासुदेव शर्मा जिस मकान में किराये से रहता है, उसी मकान में रहने वाले दूसरे किरायेदार विजय यादव ने लुटेरों को सटीक टिप दी थी। विजय को मुनीम के आने-जाने और लाखों रुपये के कैश कलेक्शन की पूरी जानकारी थी।एक ही दिन में दो व्यापारियों को मारी गोली, छत्तरूके गृहनगर में बेखौफ हुए बदमाश यह पूरी वारदात 8 जुलाई 2026 की सुबह करीब 10.30 बजे हुई थी। कुंभराज के एक बड़े धनिया व्यापारी का मुनीम वासुदेव शर्मा पचोर और गुना से कुल 17 लाख रुपये का कलेक्शन लेकर पैदल जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसकी आँखों में तीखा स्प्रे छिड़का और महज 40 सेकंड के भीतर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी अरविंद सक्सेना ने आरोपियों पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। त्वरित और बड़ी कार्रवाई में एएसपी प्रशांत सुमन, सीएसपी आनंद राय समेत कोतवाली, कैंट और साइबर सेल की टीम की सराहनीय भूमिका रही।

'इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा', मेरठ जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर से यूपी पुलिस अफसर की नोकझोंक

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुजफ्फरनगर. नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर उस समय विवादों में घिर गया, जब पुलिस ने उनके साथ चल रहे कुछ वाहनों को रोक दिया। बताया गया कि सांसद की गाड़ी टोल पार कर गई थी, लेकिन पीछे आ रही कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद सांसद स्वयं वाहन से उतरकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, बातचीत के दौरान एक इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर सांसद को स्थिति समझाने का प्रयास करता दिखाई दिया। वहीं, सांसद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगते रहे। बहस के दौरान एक इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आए और चंद्रशेखर आजाद उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाते दिखाई पड़े। इस दौरान इंस्पेक्टर ये कहता हुआ भी सुनाई पड़ा कि मैं इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा, गाली नहीं दी थी।

'एसएसपी से करेंगे मुलाकात'

रोहाना टोल पर हुए घटनाक्रम के बाद चंद्रशेखर



आजाद का काफिला मेरठ के लिए रवाना हो गया। उनका कहना है कि वह मेरठ में हाल ही में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन लोगों और उनके परिजनों से भी मिलेंगे, जो इस प्रकरण से प्रभावित बताए जा रहे हैं।

'लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने जा रहे हैं'

सांसद ने कहा कि वह किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने जा रहे हैं। उनके अनुसार, देश जानता है कि मेरठ में क्या हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का आचरण मर्यादित होना चाहिए। यदि जनता के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो लोगों के मन में भय और अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है।

'आवाज उठाना जनप्रतिनिधि का काम'

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। वह संबंधित अधिकारियों से मिलकर यह जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी और इसके पीछे क्या कारण रहे?

'इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए'

रोहाना टोल पर काफिले को रोके जाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को रोका गया है, तो उसके पीछे स्पष्ट कारण बताया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल इतना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो और जो दोषी हो, उसके विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए।

टीचर से बोला झूठ, बस में बैठी और फिर...ऐसे मिली एयरफोर्स अफसर की लापता बेटी



महानगर मेट्रो ब्यूरो

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एयरफोर्स अधिकारी की 12 वर्षीय बेटी स्कूल से अचानक लापता हो गई, जिससे परिवार और स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. छात्रा ने टीचर को झूठ बोलकर स्कूल से बाहर जाने की अनुमति ली और अपनी बस की बजाय दूसरी स्कूल बस में बैठकर निकल गई. मामला सामने आते ही महाराजपुरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर महज चार घंटे में करीब 7 किलोमीटर दूर जहांगीरपुर हाईवे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि छात्रा स्कूल से अकेले क्यों निकली और इसके पीछे क्या वजह थी. दरअसल मामला ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के स्कूल का है, जहां सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा छुट्टी के बाद अपनी स्कूल बस में बैठने के बजाय दूसरी बस में सवार होकर बाहर निकल गई. उसने टीचर से कहा कि उसके माता-पिता सूर्य मंदिर गए हैं और वह भी वहीं जा रही है. जब टीचर ने परिजनों से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा, तो छात्रा ने गलत नंबर लिख दिया. कॉल करने पर सच्चाई सामने आई और तुरंत स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी.सूचना मिलते ही महाराजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान छात्रा का बैग जड़ेरुआ बांध के पास मिला,जिससे पुलिस ने तलाशी का दायरा बढ़ाया. लगातार लोकेशन ट्रेस और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस टीम ने करीब चार घंटे की तलाश के बाद महाराजपुरा क्षेत्र के जहांगीरपुर हाईवे से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया .पुलिस के अनुसार छात्रा सुरक्षित है और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है. समय रहते स्कूल प्रबंधन द्वारा सूचना देने और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित तलाश लिया.

आजमगढ़ में आधी रात खूनी तांडवः पहले ट्यूबवेल पर दादा का गला काटा, फिर घर में घुसकर पोते को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट

महानगर मेट्रो ब्यूरो

आजमगढ़। गुरुवार देर रात बदमाशों ने 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद यादव और उनके 25 वर्षीय पोते अंकित की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी. घटना के पीछे पड़ोसियों से पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर जांच शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ही परिवार पर ऐसा कहर टूटा, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. आधी रात बदमाशों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की गला काटकर हत्या की, फिर कुछ ही मिनटों बाद घर पहुंचकर उनके पोते को भी कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया. आखिर इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कौन है? क्या पुरानी रंजिश ने दो जिंदगियां निगल लीं? पुलिस जांच कर रही है. पूरा मामला पवई थाना क्षेत्र के हेवती डिहवा गांव का है. यहां गुरुवार देर रात दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. बदमाशों ने सबसे पहले ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद यादव की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद करीब चार सौ मीटर दूर उनके घर पहुंचे और बरामदे में सो रहे उनके 25 वर्षीय पोते श्रीवांशु



यादव उर्फ अंकित पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी भी हत्या कर दी. घटना रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. अंकित के पास सो रही उसकी दादी फूलकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी. उन्होंने अंकित को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद घर के अंदर सो रहे अन्य परिजनों को जगाया गया. जब परिवार के लोग बाहर निकले तो अंकित खून से लथपथ पड़ा मिला. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से लौटने के बाद परिजन जब ट्यूबवेल पर सो रहे जगदंबा प्रसाद यादव को बुलाने पहुंचे, तो वहां का मंजर और भी भयावह था. उनका शव खून से लथपथ पड़ा था और गला काटकर उनकी भी हत्या की जा चुकी थी. एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. उधर, सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने घर से करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. मृतक अंकित के भाई शिव कुमार यादव का आरोप है कि पड़ोसियों के साथ लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में दादा और भाई की हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि अंकित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और करीब तीन महीने पहले ही घर लौटा था. मामले में एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद सहित हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ा शख्स, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा



महानगर मेट्रो ब्यूरो

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले स्थित इटारसी रेलवे जंक्शन पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. आउटर पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक युवक ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) लाइन की चपेट में आ गया. हाई वोल्टेज करंट लगते ही तेज धमाका हुआ और युवक ट्रेन की छत से नीचे गिर पड़ा. इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय धन बहादुर के रूप में हुई है. वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ गोवा जा रहा था. उसके साथ पत्नी नेहा और दो छोटे बच्चे भी यात्रा कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन इटारसी स्टेशन से आगे सी-केबिन के पास आउटर सिग्नल पर खड़ी थी. इसी दौरान धन बहादुर अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ गया. वहां मौजूद लोग उसे नीचे उतरने की आवाजें लगाते रहे, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने हाथ ओएचई लाइन के करीब पहुंचा दिया. हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आते ही जोरदार धमाका हुआ और वह नीचे गिर गया. हादसे के तुरंत बाद रेलवे पुलिस, स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने घायल युवक को इटारसी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि युवक करीब 70 प्रतिशत से अधिक झुलस चुका है. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. घायल की पत्नी नेहा ने बताया कि दिल्ली से यात्रा शुरू करने के बाद से ही उसके पति का व्यवहार असामान्य हो गया था. वह रास्ते भर उल्टी-सीधी और बेसिर-पैर की बातें कर रहा था. परिवार पहले शिमला से दिल्ली पहुंचा था और वहां से गोवा के लिए रवाना हुआ था. इटारसी के पास अचानक वह ट्रेन की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया.

AI से बनाई 'सरकारी बेवसाइट', हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम पर लाखों की ठगी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

बिजनौर। पुलिस ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी साइट बनाकर 15 राज्यों के लोगों को निशाना बनाया. पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की है. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन Cy-Vajra' के तहत बिजनौर पुलिस ने एक ऐसे संगठित साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुकिंग के नाम पर देशभर के लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिया. नूरपुर पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और नकदी भी बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक,



महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर समेत देश के 15 राज्यों से कुल 29 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुई थीं. इन शिकायतों के विश्लेषण के दौरान यह सामने आया कि कुछ साइबर अपराधियों ने परिवहन विभाग की आधिकारिक HSRP वेबसाइट की हूबहू नकल कर bookkhsrplate.com और bookmyh-srp.com जैसी फर्जी वेबसाइटें तैयार कर रखी थीं. इन वेबसाइटों के माध्यम से आम नागरिकों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन भुगतान कराया जाता था और रकम ठग ली जाती थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नूरपुर में 8 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद 9 जुलाई को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के मुख्य संचालकों में तुषार शर्मा और अरशद शामिल थे. आरोपियों ने GoDaddy के माध्यम से डोमेन और होस्टिंग खरीदी तथा AI आधारित तकनीकी संसाधनों, जिनमें ChatGPT सहित अन्य ऑनलाइन टूल्स भी शामिल थे, की सहायता से ऐसी वेबसाइटें विकसित की जो देखने में बिल्कुल सरकारी पोर्टल जैसी लगती थी. इसी वजह से लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे और ऑनलाइन भुगतान कर देते थे. जांच में यह भी सामने आया कि वेबसाइट पर प्राप्त होने वाली रकम मोहित कुमार, अनस, प्रशांत कुमार और मोहम्मद फैजान के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी. बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले लोगों को कमीशन दिया जाता था. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य बैंक खातों और संभावित आरोपियों की भी विस्तृत जांच कर रही है.

महानगर मेट्रो
www.mahanagarmetro.com

घटिया मटीरियल ने दिल्ली के रोहिणी में छीन ली 3 जिंदगी, 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-16 में 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में मृतकों की संख्या तीन हो गई है। राहत और बचाव दल ने बुधवार देर रात मलबे से मकान मालिक राम दुआ (62) और यूपी के बहराइच निवासी मजदूर नूरुल हुदा उर्फ कैफ (24) के शव बरामद किए। गुरुवार सुबह तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा मलबा हटाकर यह सुनिश्चित कर लिया गया कि उसके नीचे कोई और व्यक्ति नहीं दबा है। रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि हादसे में घायल रवि (35) और मोहम्मद सद्दाम (32) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठेकेदार घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश जारी है। शुरुआती जांच में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए मटीरियल की क्वॉलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक, सबसे पहले मलबे से बाइक मिकैनिक राम किशोर और उनके दोस्त रवि को निकाला गया। राम किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद घायल मजदूर सद्दाम को बाहर निकाला गया। देर रात 12:45 बजे नूरुल हुदा का शव और करीब 2:30 बजे मकान मालिक राम दुआ का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया है कि 26-26 गज के दो प्लॉटों को मिलाकर करीब एक साल से यह 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और ऊपर 4 मंजिलो पर फ्लैट तैयार किए जा रहे थे। अगले महीने परिवार के नए मकान में शिफ्ट होने की प्लानिंग थी। बारिश के कारण बुधवार को केवल पीओपी का काम करने वाले दो मजदूर नुरुल हुदा और सद्दाम ही साइट पर पहुंचे थे। दोपहर में खाना खाने के बाद राम दुआ भी काम देखने पहुंचे थे। इसी दौरान करीब 4:20 बजे पूरी इमारत भरभराकर गिर गई।



CM रेखा गुप्ता ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, मंडी रोड को नेशनल हाईवे बनाने की मांग



महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली की ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की औपचारिक मांग की है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि करीब 8.8 किलोमीटर लंबी इस बेहद महत्वपूर्ण मांडी रोड का आगामी विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाए. मुख्यमंत्री का मानना है कि सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर एनएचएआई को सौंपने से इस पूरे रूट का एक एकीकृत विकास सुनिश्चित हो सकेगा भौगोलिक और यातायात के नजरिए से देखा जाए तो मांडी रोड की भूमिका दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहद अनूठी है. यह सड़क छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास नेशनल हाईवे-148ए से शुरू होती है और दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सीधे गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ती है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात को रेखांकित किया है कि यह सड़क केवल स्थानीय यातायात के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच अंतरराज्यीय यातायात के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक कॉरिडोर के रूप में काम करती है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 सितंबर 2023 को आयोजित की गई यूटीटीआईपीईसी की 68वीं महत्वपूर्ण बैठक में भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया गया था. उस बैठक में भी मांडी रोड के चौड़ीकरण और विकास के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया गया था. अब दिल्ली सरकार इस योजना को और गति देते हुए इसे सीधे केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधीन लाना चाहती है ताकि फंड और तकनीकी अड़चनों के बिना काम तेजी से आगे बढ़ सके. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील होने से न केवल दिल्ली-एनसीआर का लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि इसका सीधा सकारात्मक असर दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच रोजाना अप-डाउन करने वाले नौकरीपेशा लोगों और आम जनता पर पड़ेगा. इसके बनने से यात्रा के समय में भारी कमी आएगी और छतरपुर व मेहरौली रोड पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगी.

दिल्ली में लगेगी 'गुड टच-बैड टच' की क्लास... स्कूलों में मनेगा POCSO जागरूकता माह

दिल्ली सरकार ने जुलाई को POCSO जागरूकता माह घोषित किया है, जिसमें सभी स्कूलों में बच्चों के लिए गुड टच-बैड टच पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे.

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने पूरे जुलाई महीने को 'POCSO जागरूकता माह' के रूप में मनाने का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि यह केवल एक जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखने की व्यापक पहल है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, जुलाई के दौरान दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में बच्चों के लिए 'गुड टच' और 'बैड टच' पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों के माध्यम से बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप सरल भाषा में यह समझाया जाएगा कि कौन-सा व्यवहार सुरक्षित है, कौन-सा असुरक्षित है और किसी भी गलत व्यवहार की स्थिति में उन्हें किससे और कैसे मदद मांगनी चाहिए. सरकार ने सभी स्कूलों में बाल सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश भी दिए हैं. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन हो. अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और 15 दिनों के भीतर अनुपालन (कंप्लायंस) रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. इस अभियान को केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रखा गया है. इसे एक व्यापक सामाजिक अभियान के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें अभिभावकों, शिक्षकों, दिल्ली पुलिस, जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. सरकार का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य पूरे दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत जन-जागरूकता अभियान खड़ा करना है, ताकि हर बच्चा सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सके और किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में बिना डर अपनी बात कह सके. बीते वर्षों में हुई संगीन घटनाओं से लिया.



देवेंद्र फडणवीस के 'देख लूंगा' वाले बयान पर भड़के MNS प्रमुख राज ठाकरे, कहा- महाराष्ट्र CM को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की 'मिसिंग लिंक' सुरंग में हाल ही में हुए पानी के रिसाव को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला उन्होंने मुख्यमंत्री के 'देख लूंगा' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती

महानगर मेट्रो ब्यूरो



मुंबई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की 'मिसिंग लिंक' सुरंग में हाल ही में हुए पानी के रिसाव को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को महायुति सरकार पर भावनात्मक बयानबाजी के पीछे अपनी नाकामियों को छिपाने का आरोप लगाया। एमएनएस रेलवे कामगार सेना की वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए मनसे प्रमुख ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के बचाव पर सवाल उठाया और विपक्ष को इस मुद्दे का 'राजनीतिकरण' न करने की चेतावनी देने वाली उनकी टिप्पणी पर पलटवार किया। विपक्ष की आलोचना पर मुख्यमंत्री फडणवीस की आपत्ति पर तंज कसते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वाह! वे (देवेंद्र फडणवीस) कहते हैं कि इसे राजनीतिक रंग मत दो। जब कोई बोलता है, तो उनके लिए यह 'राजनीति' बन जाती है। विपक्ष में रहते हुए आप इतने सालों तक क्या कर रहे थे? पिछली सरकारों के खिलाफ आपने जो आंदोलन किए, क्या वे 'राजनीति' नहीं थे? अब जब आप पर दबाव बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिसिंग लिंक पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो सकता है? 2008 के रेलवे भर्ती आंदोलन को याद करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उसी आंदोलन से मनसे को पहचान मिली और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रेल इंजन बना। रेलवे में मराठी युवाओं को रोजगार मिले, इसी उद्देश्य से आंदोलन किया गया था। महाराष्ट्र में रेलवे की भर्ती होने के बावजूद उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश और बिहार के अखबारों में छपती थी, महाराष्ट्र के युवाओं तक नहीं पहुंचती थी। आंदोलन के बाद स्थानीय भाषा में परीक्षा देने की सुविधा शुरू हुई, जिससे हजारों मराठी युवाओं को नौकरी मिली।उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि रेलवे की भर्ती, प्लेटफॉर्म पर स्टॉल आवंटन और रेलवे में कौन नौकरी कर रहा है, इस पर लगातार नजर रखें। 'जागे रहो, सतर्क रहो, बेसावध मत रहो।' मुख्यमंत्री के 'देख लूंगा' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए मनसे अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री का हिंदी में दिया गया बयान महाराष्ट्र के विधायकों के लिए था या दिल्ली के नेताओं के लिए, यह भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए कहना चाहिए था कि वे मामले में हस्तक्षेप करेंगे और काम पूरा करवाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई-पुणे का विकास पूरी तरह बिगड़ चुका है और इसे विकास बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री से अपील की कि फिलहाल सभी निर्माण कार्य रोककर पहले शहर की व्यवस्था सुधारें। उन्होंने कहा कि 1 मई को उद्घाटन हुआ और कुछ ही दिनों में टनल से पानी टपकने लगा और हिस्से गिरने लगे। आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण घटिया निर्माण हो रहा है.

अगले दो सप्ताह कम होगी बारिश पर बढ़ेगा तापमान, महाराष्ट्र में कब तक रहेगा ऐसा मौसम

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। मुंबईकरों समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बारिश की रफ्तार कम हो गई है। इसकी घोषणा मौसम विभाग ने की है। दरअसल गुरुवार को पूरे भारत में मॉनसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की गई। इससे राहत और खुशी तो मिली, लेकिन अगले दो सप्ताह के पूर्वानुमान बताते हैं कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की रफ्तार धीमी रहेगी। कोंकण डिवीजन में 23 जुलाई तक औसत से कम बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के दो सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में 23 जुलाई तक हल्की बारिश होने की संभावना है और इस दौरान बारिश औसत से काफी कम रहेगी। 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच दक्षिण कोंकण के कुछ इलाकों में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। हालांकि, इस बारे में साफ तस्वीर 16 जुलाई तक सामने आने की उम्मीद है। पहले सप्ताह (9-16 जुलाई) के दौरान विदर्भ के कुछ इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है।



उत्तर, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कैसी बारिश?

इसी तरह 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच उत्तर-मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। हालांकि मौजूदा मॉडल बताते हैं कि यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 जुलाई तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा डिवीजन में हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

कोंकण डिवीजन में बारिश की रफ्तार कम होने के तुरंत बाद गुरुवार को तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। अलीबाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। मुंबई में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। कोलाबा में 30.5एष्ट और सांताक्रूज में 31.4एष्ट तापमान दर्ज किया गया।

मुंबई लोकल ट्रेनों में रुकावट

वसई-विरार सेक्शन में भारी बारिश और उसके बाद जलभराव के कारण मुंबई की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं में बड़ी रुकावटें आईं। वेस्टर्न रेलवे ने पानी जमा होने से रोकने के लिए पटरियों की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया है। वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रामाश्रय पांडे ने हाल ही में डिवीन का निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

शरद पवार-एकनाथ शिंदे के बाद अब सुनेत्रा पवार-देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, महाराष्ट्र में बढ़ी राजनीतिक हलचल

स्वर्ण खबर डेस्क

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा ने फडणवीस को पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है। साथ ही यह भी बता दिया है कि शरद गुट के विलय की स्थिति में पार्टी का रुख क्या है और उन्हें एनडीए में शामिल करने पर पार्टी का रुख क्या होगा। सीएम फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में अब सीट खाली नहीं है।



राजनीतिक हलकों में हलचल

वहीं जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं की यह मुलाकातें भले ही एक शिष्टाचार भेंट लग रही हो लेकिन इसके समय और तरीके को देखकर राजनीतिक हलकों में गहरी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और शिंदे की मुलाकात के बाद जहां उद्धव सेना ने इसकी तीखी आलोचना की है। संजय राउत ने कहा कि हमारी सरकार गिराने वाले गद्दार के कार्यालय में मीटिंग करना बड़े नेताओं की साख कम करता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि शरद पवार के 5 से 6 सांसद असहज हैं, पवार की पार्टी का भी उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हाल हो सकता है। पवार के सांसद असहज हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि वे पार्टी छोड़ेंगे या नहीं। लगातार हो रही राजनीतिक मुलाकातों के बाद एक बार फिर दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी शरद पवार गुट के कांग्रेस में विलय के प्रस्ताव को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला है। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि दोनों एनसीपी में विलय के बाद शरद पवार अपने लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सीनियर के नेताओं ने इन सभी चर्चाओं को साफ तौर पर खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद अफवाह बताया है। विधायक रोहित पवार ने साफ किया कि एनडीए में शामिल होने को लेकर चल रही सभी चर्चाएं बेबुनियाद हैं। शरद पवार के एकनाथ शिंदे की ऑफिस में जाकर मीटिंग करने पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं लेकिन एकनाथ शिंदे के दफ्तर में पार्टी बैठक करना उचित नहीं था। जिन लोगों ने सरकार गिराई और गद्दारी की, उन्हें इस तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा देना गलत संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यदि शिवसेना की स्थिति ऐसी होती तो वह कभी भी गद्दारों के परिसर में पार्टी बैठक नहीं करती।

दिल्ली में पिंक कार्ड को लेकर आया नया अपडेट, फ्री बस सफर को लेकर महिलाओं के लिए जरूरी खबर

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। अगर आप डीटीसी की बसों में सफर करती हैं और अभी तक सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। क्योंकि बसों में महिलाओं को पिंक टिकट नहीं मिलेगा। बस में मुफ्त सफर के लिए सहेली पिंक कार्ड अनिवार्य होगा। जिसे टैप करके मुफ्त यात्रा की सुविधा ले सकेंगी। दिल्ली में मार्च से अब तक कुल 10 लाख से अधिक महिलाएं अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बना चुकी है। डीटीसी अधिकारियों के अनुसार बसों में रोजाना औसतन 6-7 लाख महिलाएं सफर करती हैं। हालांकि अभी तक 10 लाख से अधिक महिलाएं, यह कार्ड बनवा चुकी हैं। लेकिन देखने में आया है कि कुछ महिलाएं अभी भी बिना पिंक कार्ड के सफर कर रही हैं। महिलाओं में से 15-20 फीसदी ही महिलाएं सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड से सफर कर रही है। यानी बाकी महिलाएं पिंक टिकट लेकर चल कर ही है। जबकि परिवहन विभाग की ओर से बार-बार महिलाओं से पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने की अपील की जा रही है। सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में पर्याप्त संख्या में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बन चुके है। फिर भी किसी को दिक्कत न हो इसलिए कार्ड बनवाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। हमने 31 जुलाई तक का समय तय किया है कि उसके बाद सिर्फ सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के जरिए ही महिलाएं बस में मुफ्त सफर कर पाएंगी। डीटीसी उससे पहले महिला यात्रियों को सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए जागरूक भी करेगी। दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त सफर की योजना 2019 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शुरू किया था। मौजूदा सरकार ने भी 2026-27 में इसके लिए 450 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मार्च से 58 सेंटर्स पर पिंक स्मार्ट कार्ड बनाने का काम चल रहा है।



दिल्ली में 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं अपना पिंक स्मार्ट कार्ड बन सकती है। इसके लिए दिल्ली का आधार नंबर जरूरी है।ईस्ट विनोद नगर

आवेदक महिला या लड़की की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए? दस्तावेज के रूप में केवल दिल्ली का मूल आधार कार्ड लगेगा वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको स्वयं केंद्र पर जाना होगा

बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव मुश्किल में हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सज़ा बरकरार रखी, मुश्किलें बढ़ीं!

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली/मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव के लिए कानूनी मोर्चे पर बहुत बुरी खबर है। फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव अब असल ज़िंदगी में कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। करोड़ों रुपये के चेक बाउंस के एक हाई-प्रोफाइल मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर राजपाल यादव पर सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद राजपाल यादव की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने पाया कि सेशंस कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता को पहले ही किए गए भुगतान को ठीक से ध्यान में रखा था। इन सभी पहलुओं की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि जुर्माना तय करते समय ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई कानूनी गलती नहीं हुई थी, इसलिए सज़ा में कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह मामला एक बड़े वित्तीय लेन-देन और लोन से जुड़ा है। राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपये का लोन लिया था। इस लोन को चुकाने के लिए उन्होंने जो चेक दिए थे, वे बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण बाउंस हो गए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी पाया और उन्हें सज़ा और जुर्माना सुनाया।

कानून सभी के लिए एक है: सेलिब्रिटी होने के बावजूद कोई राहत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि कानून की नज़र में सेलिब्रिटी और आम आदमी के बीच कोई अंतर नहीं है। करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव को अब कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। 'पक्को गुजरात' अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के बाद बॉलीवुड गलियारों में वित्तीय लेन-देन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब यह देखना बाकी है कि राजपाल यादव इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या हाई कोर्ट के आदेश के आगे सरेंडर करते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई के लिए किया बड़ा ऐलान, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके करेंगे अगुआई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को 20 दिन हो गए है। इसी के साथ 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसकी अगुवाई सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके करेंगे। इसके बाद अभिजीत दीपके ने लोगों से 20 जुलाई के मार्च में शामिल होने की अपील की। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर यह मार्च निकालेगा। शिक्षा के मुद्दे पर धरने के 20 दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि वांगचुक के अनशन का 12वां दिन है। पार्टी के अनुसार, इस दौरान उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।



पुलिस ने तिरपाल अंदर नहीं ले जाने दिया

वहीं, उधर, पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जंतर मंतर पर जलभराव के हालात बन गए है। प्रदर्शनकारियों के गद्दे और मंच भीग गए है और कई जगह पानी भर गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि बारिश से बचाव के लिए वॉटरप्रूफ तिरपाल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस को पत्र भी दिया गया है, लेकिन पिछले तीन दिन से इजाजत नहीं मिली।

दिल्ली पुलिस और कॉकरोच के सदस्यों के बीच जमकर बहस

दिल्ली पुलिस ने अपने लिए टेंट लगाए है, जबकि प्रदर्शनकारियों को तिरपाल तक अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहसबाजी हुई। अभिजीत दिपके पुलिस अधिकारियों के सामने बैठकर और झुककर तिरपाल अंदर ले जाने की इजाजत देने का अनुरोध करते नजर आए। बाद में दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। मौके पर बड़ी संख्या में रैपिड ऐक्शन फोर्स तैनात रही।

विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के खिलाफ विशाल विरोध रैली

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पालनपुर/बनासकांठा। बनासकांठा की शांतिपूर्ण धरती को आतंकवाद के काले साये से बचाने और देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए पालनपुर में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा गया। हाल ही में गुजरात ATS ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' से जुड़े 8 आतंकवादियों को राज्य भर से, जिसमें पालनपुर बॉर्डर भी शामिल है, गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से हिंदू संगठन सतर्क हो गए हैं। इन देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पालनपुर में एक विशाल 'विरोध रैली' आयोजित की। देश-विरोधी तत्वों की कड़ी आलोचना करते हुए ज़िला कलेक्टर को एक शिकायत भी भेजी गई। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि पालनपुर तालुका हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन यहाँ के भागल गाँव में चार असामाजिक तत्व पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर देश को अस्थिर करने की बड़ी साज़िश रच रहे थे। गुजरात ATS की टीम ने ऑपरेशन चलाकर इन आतंकवादियों को पकड़ा। इतना ही नहीं, जब इन देशद्रोहियों के घरों की तलाशी ली गई, तो बड़ी संख्या में देश-विरोधी और आपत्तिजनक दस्तावेज़ मिले। जैसे ही यह घटना सामने आई, पालनपुर समेत पूरे बनासकांठा में भारी गुस्सा और आक्रोश फैल गया। आस-पास के गाँवों में संदिग्ध मदरसों और मुस्लिम इलाकों में किराए पर रहने वाले संदिग्ध लोगों की तुरंत जाँच होनी चाहिए।



गुजरात के शहरी विकास का स्वर्णिम युगः मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ऐतिहासिक फ़ैसला,

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गांधीनगर। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने गुजरात के शहरी इलाकों के आधुनिकीकरण और नागरिकों की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी ऐतिहासिक फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 9 नई नगरपालिकाओं के सर्वांगीण और तेज़ विकास को गति देने के लिए एक मास्टर प्लान की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फ़ैसले के अनुसार, राज्य की इन नौ नई नगरपालिकाओं को अगले पाँच वर्षों के लिए जनहित से जुड़े 11 अलग-अलग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए ज़रूरी सरकारी ज़मीन बिना किसी लागत के, यानी बिल्कुल मुफ़्त दी जाएगी। सरकार का यह कदम स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को ज़बरदस्त बढ़ावा देगा। राज्य सरकार के इस कल्याणकारी फ़ैसले का सीधा लाभ गुजरात के अलग-अलग ज़ोन में स्थित इन नई बनी नगरपालिकाओं को मिलेगाः

1. वापी, 2. मेहसाणा, 3. पोरबंदर, 4. मोरबी, 5. गांधीधाम, 6. नडियाद, 7. आनंद, 8. नवसारी, 9. सुरेंद्रनगर, किन 11 महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के लिए मुफ़्त ज़मीन मिलेगी?

नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने 11 सबसे ज़रूरी सुविधाओं के लिए मुफ़्त ज़मीन देने को मंज़ूरी दी है, जिनमें ये शामिल हैं नगर सेवा सदनः नगरपालिका की एक आधुनिक ऑफ़िस बिल्डिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), अंडरग्राउंड सीवर ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन और जलापूर्ति प्रोजेक्ट (पानी की सप्लाई के काम) साफ़-सफ़ाई और पर्यावरणः सॉलिड/लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और साथ ही बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज। सामाजिक और सांस्कृतिक विकासः बच्चों के लिए बालवाड़ी (आंगनवाड़ी) और साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल और कन्वेंशन सेंटर। करोड़ों रुपये का बोझ कम होगा, विकास की रफ़्तार तेज़ होगी।

CHO रेगुलर हुए तो अब FHW बंदूकधारी बन गए हैं आम जनता रामभरोसे



महानगर मेट्रो ब्यूरो

बनासकांठा। दांता और हडाद तालुका के आसपास इलाकों में सरकारी हेल्थ सुविधाओं की गंभीर हालत के बारे में 'पाको गुजरात' द्वारा किए गए एक खास रियलिटी चेक में चौंकाने वाला मामला सामने आया है इन दोनों तालुकाओं में एक ही रात में तेरह लोगों की मौत की पुष्टि होने पर हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। लंबे समय से चल रहे विवादों और रिप्रेजेंटेशन के बाद अब जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ड्यूटी पर कायमी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ, फीमेल हेल्थ वर्कर अब खुलेआम गोली चलाने लगी हैं। जब हमारे प्रतिनिधियों ने दांता और हडाद तालुका के दूर-दराज के गांवों में सरप्राइज रियलिटी चेक के लिए अलग-अलग सब-सेंटर और हेल्थ सेंटर का दौरा किया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की धज्जियां उड़ती दिखीं। कई सेंटर पर ड्यूटी पर मौजूद फीमेल हेल्थ वर्कर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं थीं। स्थानीय लोगों ने गुस्से में कहा कि इन इलाकों में ड्यूटी पर मौजूद FHW सिर्फ दिखावा है वे कभी-कभी सिर्फ़ अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए सेंटर पर आते हैं और अपने इलाकों में घूमने के बाद कुछ ही मिनटों में खानापूर्ति करके गायब हो जाते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मतती और क्या हो सकती है कि ये सरकारी कर्मचारी, जिन्हें सरकार से हर महीने हज़ारों-लाखों रुपये की मोटी सैलरी मिलती हैं।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने देश लौटने का किया ऐलान

वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वापस लौटूंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने देश लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लौटूंगी। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर-2026 के आसपास बांग्लादेश वापस जाएंगी और कोर्ट में सरेंडर करेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक घंटे के टेलीफोन इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा पता है, लेकिन यह भी पता है कि अब उनके अपने देश लौटने का समय आ गया है। शेख हसीना ने भावुक होते हुए कहा कि अगर उनकी मौत होती है तो वह अपने देश की मिट्टी पर हो, जहां उनके माता-पिता दफन हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त दमन हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिसंबर के आसपास भारत में अपने निर्वासन से वापस लौटने और सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण एशियाई देश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहीं इस शेख हसीना ने कहा कि वह और उनकी अवामी लीग के सदस्य स्वेच्छा से उस देश लौटना चाहते हैं। देश लौटने के बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शेख हसीना कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती हैं। उन्हें बांग्लादेश की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं शेख हसीना की अवामी लीग पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस साल हुए संसदीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। बता दें दो साल पहले बांग्लादेश और अपना पद छोड़कर भारत शेख हसीना भारत आ गई थीं अब कोर्ट में पेश होना चाहती हैं।

शेख हसीना ने गुरुवार देर रात एक मीडिया से करीब एक घंटे तक टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, यहां तक कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा फिर भी मुझे जाना ही है। शेख हसीना अगर बांग्लादेश लौटती हैं तो इस साल पीएम बने तारिक रहमान के लिए उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। इस साल हुए चुनाव से साफ हो गया है कि शेख हसीना के पास अभी भी देश में भारी समर्थन है। तारिक रहमान करीब दो सालों के अंतरिम सरकार के बाद अब देश में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शेख हसीना के लौटने से उनके समर्थकों में फिर से जोश आ सकता है और वह एक बार फिर से देश की राजनीति पर हावी हो सकती हैं। शेख हसीना को गिरफ्तार करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा।

शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना की प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही हैं लेकिन भारत सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करेगी इसकी संभावना कम ही है। उन्होंने कहा ढाका के अधिकारी मुझे भारत से वापस ले जाना चाहते हैं। वह लगातार भारत सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं जिसमें वह मेरे प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार है जब उन्होंने अपनी वापसी के लिए कोई समय-सीमा बताई है और कहा है कि वह आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं या अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेता ऐसा करेंगे। इनमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल भी शामिल हैं जिन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है।



हिमाचल में आफत की बारिश, लोहे का बेली ब्रिज पानी में डूबा, घरों में भरा पानी

शिमला (एजेंसी)। शिमला और राज्य के कई हिस्सों में फिर बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक गुरुवार को बारिश की वजह से 75 सड़कें बंद हो गई थीं। बिजली वितरण के 29 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए और पानी की सप्लाई की पांच योजनाएं बाधित हुईं। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि सोलन में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, हमीरपुर और चंबा में मध्यम बारिश; कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश; और लाहौल-स्पीति में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों तक शिमला में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ कहीं-कहीं तेज बारिश का दौर जारी रहने की बहुत संभावना है, जिसके बाद बारिश धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। किन्नौर जिले के पूह उपमंडल के लिप्पा में वीरवार सुबह बारिश के बाद पेजर नाले में बाढ़ के साथ आए मलबे से तेती खड्ड का बहाव रुक गया। इससे लिप्पा गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फीट लंबा लोहे का बेली ब्रिज पानी में डूब गया। पुल बंद होने से सड़क संपर्क बाधित हुआ। पुल के समीप 12 मकानों तक बाढ़ का पानी पहुंचने से 13 परिवार प्रभावित हुए। प्रशासन ने इन्हें जीरा फार्म में शिफ्ट कर भोजन की व्यवस्था की। मलिंग नाला के समीप भूस्खलन से रामपुर-किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। शिमला के अंतर्गत आकलैंड में डंगा गिरने से पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वीरवार सुबह चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुमारहट्टी के समीप, परवाणू से कंडाघाट तक जगह-जगह पहाड़ी से पत्थर गिरते रहे। सोलन में वर्षा के बाद सब्जी मंडी में पानी भर गया। चंबा जिले की कीड़ी पंचायत के गांव कपड़ौथा में पहाड़ी से मलबा व पत्थर एक मकान के पीछे गिरे। परिवार ने भाग कर जान बचाई और रात रिश्तेदारों के घर बिताई, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया।

टीएमसी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन



-पार्टी ने तीनों को राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तीनों को बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। तीनों ने ममता से नाराजगी जताई थी और कहा था कि पार्टी मनमाने ढंग से चल रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुखेंदु राय ने 8 जून, सुष्मिता ने 10 जून और प्रकाश ने 11 जून को रिजाइन दिया था। बंगाल की इन तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। 14 जुलाई नामांकन दाखिल होगा और नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी।

सुखेंदु रॉय ने कहा कि आरजी कर रेप-मर्डर केस में सबूतों से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाने के बाद मुझे जान से मारने और परिवार के अपहरण की धमकियां मिलने लगीं। पुलिस आयुक्त और अस्पताल के प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग करने के बाद उन्हें लालबाजार पुलिस मुख्यालय भी बुलाया गया। खराब तबीयत के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा।

सुष्मिता देव ने बताया कि पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा में बीजेपी की जीत से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा दिखता है। असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना इसकी बड़ी मिसाल है। महुआ मोइत्रा को कोई दूसरी पार्टी अपने साथ नहीं लेना चाहती, इसलिए वह टीएमसी में हैं।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय तीनों नेता पहले से ही बीजेपी के साथ थे। अब अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। इससे टीएमसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी को भी इससे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दल बदलने वाले नेताओं की ज्यादा अहमियत नहीं होती है।

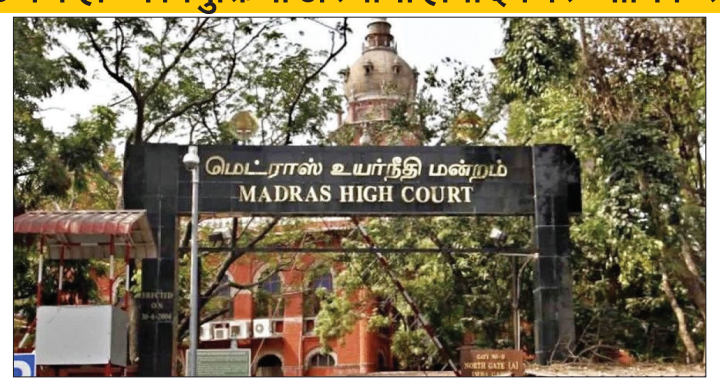
करूर भगदड़ में मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की सरकार को मिली मंजूरी

-मद्रास हाईकोर्ट ने कहा-ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी इन पर न्यायिक समीक्षा लागू होगी

चेन्नई (एजेंसी)। करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु सरकार को राहत मिल गई है। अब करूर भगदड़ में मृतकों के परिजनों को विजय सरकार सरकारी नौकरी दे सकेगी। इसकी मद्रास हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी और इन पर न्यायिक समीक्षा लागू होगी। मदुरै बेंच के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसले में कोर्ट का दखल देना 'बहुत संकीर्ण सोच; होगी। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या सार्वजनिक त्रासदियों के पीड़ितों को दी जाने वाली नौकरियों के लिए कोई एक समान सरकारी नीति हुए बिना ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों के परिवारों को नियुक्ति पत्र देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी इजाजत दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस शर्त पर कार्यक्रम आगे बढ़ा सकती है कि नौकरी अस्थायी आधार पर होगी और उस पर न्यायिक समीक्षा लागू होगी। हमारी योजना है कि इस महीने के आखिर तक, यानी नौकरी पाने वालों को पहली सैलरी मिलने से पहले, इस मामले की सुनवाई कर ली जाए।

इस बीच तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय शुक्रवार को करूर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र और कल्याणकारी सहायता प्रदान करेंगे। सीएम विजय अपने दौरे के दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।सीएम विजय शुक्रवार सुबह हवाई मार्ग से चेन्नई से रवाना हुए और उनके तिरुचिरापल्ली (तिरुची) हवाई अड्डे पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से करूर जाएंगे। उनके स्वागत के लिए पूरे मार्ग पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत की तैयारियां की। विजय करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसके बाद वह वहां आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल बनाया गया। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए सरकारी पर्यटक गृह में रुकेंगे और फिर एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए करूर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम विजय करूर भगदड़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के पात्र सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अनुकंपा नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास उपायों के तहत दी जा रही हैं, जिनका उद्देश्य शोकाकुल परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम में वितरित की जाने वाली कल्याणकारी सहायता में विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ शामिल हैं।



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का मोदी सरकार पर हमला : चीन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा, आत्मनिर्भर भारत फेल

नई दिल्ली(एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने चीन के प्रति नरम रुख अपनाया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ी है तथा राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर यह भी दावा किया कि वर्ष 2020 में हुई गलवान की घटना के बाद वर्ष 2025-26 तक चीन से भारत का आयात 101.81 प्रतिशत बढ़ गया और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बढ़कर 112.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया, छह वर्ष पहले गलवान में 20 भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने भारत के हितों के समक्ष चीन के प्रति नरम रुख अपनाया। खरगे ने कहा कि भारत के एंटीबायोटिक आयात का 86 प्रतिशत हिस्सा चीन से आता है। उनके अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में भारत के 66 प्रतिशत पुर्जों का आयात चीन से होता है, जबकि भारतीय ईवी में इस्तेमाल होने वाली लगभग 75 प्रतिशत लिथियम-आयन बैटरियां आयातित हैं और इनमें अधिकतर चीन से आती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की निर्भरता चीन पर बनी हुई है। खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अब चार चीनी कंपनियों को सरकारी बिजली परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर चीन के लिए और अवसर खोल दिए हैं।

राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी, जनता से मांगे जा रहे सुझाव

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस सिर्फ विरोध करती

जयपुर (एजेंसी)। उत्तराखंड और गुजरात के बाद, अब राजस्थान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की तैयारी जोर-शोर से शुरु हो गई है। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रस्तावित कानून के मसौदे को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित करना शुरू किया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने इस उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और लोगों से बातचीत के माध्यम से 19 महत्वपूर्ण सवालों पर राय मांगी है। यह कदम राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मंशा को दिखाता है।

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान देकर कहा कि राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी जोरों पर है। उन्होंने बताया कि पार्टी उन



राज्यों के मौजूदा ड्राफ्ट का अध्ययन कर रही है, जहाँ यूसीसी पर काम हो चुका है, साथ ही जनता से बहुमूल्य सुझाव लिए जा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधकर आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दे रहा है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि राजस्थान में यूसीसी जल्द ही लागू किया जाएगा। जनता की राय को शामिल करते हुए, यूसीसी का ड्राफ्ट बिल राजस्थान विधानसभा के अगले सत्र में पेश होने की उम्मीद है। जिन प्रमुख प्रस्तावों पर विचार हो रहा है, उसमें लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण एक अहम मुद्दा है। समिति ने लोगों से राय मांगी है कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त होने पर तलाक से जुड़े कानूनी नियम लागू होने चाहिए। सवालों की विस्तृत सूची में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कई बिंदु शामिल हैं, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप पर विशेष जोर दिया गया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस विषय पर कोई सुझाव नहीं दे रही है।

ममता का बीजेपी को कड़ा संदेश : मुझे मारकर ही चुप कराया जा सकता

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने सीधे चुनौती दी कि अगर भाजपा उन्हें चुप कराना चाहती है, तब उन्हें उनकी जान लेनी होगी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार टीएमसी नेताओं को परेशान कर रही है और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं।

ममता का वीडियो टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में ममता ने महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि उनके घर तक पर हमला हुआ। हिरासत में लिए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र कर ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें जमीन पर सोने, कमर में रस्सी बांधकर और पैरों में बेड़ियां डालकर घुमाया जा रहा है, और कुछ का सिर मुंडवा दिया गया।

ममता ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग टीएमसी में रहने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने इसतरह के नेताओं को स्पष्ट फैसला करने को कहा या वे टीएमसी के साथ रहें या खुलकर भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुमराह न करें।

यह बयान तब आया है जब टीएमसी छोड़कर गए तीन पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। 24 जुलाई को होने वाले इन उपचुनावों में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिससे टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं।



अमेरिका के ईरान पर ताजा हमलों से भारत-चीन को भी लगा तगड़ा झटका

-शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को पहुंचा नुकसान, चीन को जोड़ने वाला पुल भी टूटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के ईरान पर किए गए नए सैन्य हमलों ने न केवल मध्य पूर्व की अस्थिरता बढ़ा दी है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर भारत और चीन जैसे प्रमुख एशियाई देशों के निवेश और हित को झटका दिया है। अमेरिका की ओर से ईरान के चाबहार पोर्ट पर किए गए हमले में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। इस टर्मिनल में भारत ने अरबों का निवेश किया है।

वहीं अमेरिका ने चीन-ईरान को जोड़ने वाले एक रेलवे पुल को भी निशाना बनाया है। यह पुल तेहरान और ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, चीन के बीच व्यापार के अहम रास्तों को जोड़ता है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान रूस को माल भेजने के लिए भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो नुकसान हैं, जिससे भारत और चीन के हित जुड़े हुए हैं। इन नुकसान के अलावा अमेरिकी हमले में ईरान को और भी क्षति हुई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट पर कई अमेरिकी मिसाइलें गिरने से उसे नुकसान पहुंचा है। इससे यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हमलों में चाबहार का वेसल ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कलंतरी पोर्ट और ओमान की खाड़ी में स्थित इस पोर्ट सिटी का बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुआ है। अमेरिकी हमलों की वजह से शहर के करीब आधे हिस्से में बिजली गुल हो गई। अमेरिकी हमले की वजह से शाहिद बेहेश्ती डॉक पर कई प्रोजेक्टाइल गिरे जिससे बंदरगाह के ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस टर्मिनल को विकसित करने के लिए अब तक 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया है और पीएम मोदी ने 2016 में इसके लिए 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार के विकास के लिए ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के साथ समझौता किया था। अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस को जोड़ने वाले एक रणनीतिक रेलवे पुल पर हमला किया। इस पुल को चीन, तुर्कमेनिस्तान और ईरान को जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर का एक रणनीतिक पॉइंट बताया गया है।

यह पुल तेहरान और ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन के बीच व्यापार के अहम रास्तों को जोड़ता है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान रूस को माल भेजने के लिए भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। इस पुल से होकर गुज़रने वाला रास्ता तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान से होते हुए चीन तक जाता है। ईरानी रेलवे ने कहा कि मरम्मत करने वाली टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है जल्द पुल की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।



आईएमएफ का अनुमान भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर

- तेज आर्थिक वृद्धि और सुधारों से भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

वाशिंगटन ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा है कि देश अपनी लगातार तेज आर्थिक वृद्धि और सतत सुधारों की बदौलत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। आईएमएफ ने भारत को वैश्विक वृद्धि का प्रमुख इंजन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया। यह टिप्पणी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के ताजा अनुमानों के एक दिन बाद आई है। आईएमएफ की संचार विभाग की एक व रिष्ठ अ धिकारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत अनुमानित है, जो 6.7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए तेज वृद्धि और निरंतर सुधार आवश्यक हैं। आईएमएफ ने कौशल विकास, श्रम बाजार लचीलापन, कारोबारी लागत में कमी और व्यापार एकीकरण जैसे सुधारों पर जोर दिया। भारत ने नए श्रम कानूनों व व्यापार समझौतों जैसे संरचनात्मक सुधारों में प्रगति की है। विनिर्माण में, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण से भारत को, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाभ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 24 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें घरेलू विनिर्माताओं की अहम भूमिका है।

कच्चे तेल में उतार चढ़ाव, 72 डॉलर के पास टिकी कीमतें

होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी निगाहें, कीमतें स्थिर

नई दिल्ली ।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें शुक्रवार को स्थिर बनी रहीं। डब्ल्यूटीआई क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर के करीब रहा। पिछले सत्र की गिरावट के बाद बाजार शांति वार्ता और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को कीमतें स्थिर रहने के बावजूद पूरे सप्ताह अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड 4 फीसदी से अधिक की बढ़त की ओर बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ा सैन्य तनाव रहा, जब अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इन घटनाओं ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर चिंता बढ़ा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां एक तरफ अंतरिम शांति समझौते को खत्म बताया, वहीं बातचीत जारी रहने की पुष्टि भी की। बाजार इन्हीं मिश्रित संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि, सबसे बड़ी चिंता अभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य है, जहां से दुनिया का बड़ा समुद्री तेल व्यापार गुजरता है। तनाव के कारण यहां टैंकरों की आवाजाही धीमी बनी हुई है। यदि यह स्थिति लंबी खिंचती है, तो भविष्य में वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतों में फिर उछाल आ सकता है।

डॉ. रेड्डीज के सेमाग्लूटाइड उत्पादन में एपीआई गुणवत्ता बनी बाधा

- सीईओ ने कहा, आपूर्ति अक्टूबर-नवंबर तक टली

नई दिल्ली ।

दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) वित्त वर्ष 2027 के लिए 120 लाख सेमाग्लूटाइड पेन का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी।

दवा में प्रयुक्त सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (एपीआई) में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे कंपनी के उत्पादन समय-सीमा पर असर पड़ा है। कंपनी के एक अ धिकारी ने निवेशकों को बताया कि एपीआई समस्या के कारण उत्पादन में बाधा आई है। अब कंपनी वित्त वर्ष 2027 की तीसरी और चौथी तिमाही में पहले से बिके पेनों के अतिरिक्त केवल 60 से 70 लाख पेन ही उत्पादित कर पाएगी।

नियामकीय फाइलिंग में बताया गया कि उत्पादन बढ़ाने हेतु उपयोग किए गए एपीआई के एक विशेष बैच में गुणवत्ता संबंधी दिक्कतें मिलीं, जिससे कुछ सेमाग्लूटाइड बैच मानकों से हटकर पाए गए। इजरायली ने इसे एपीआई में किसी प्रतिक्रिया प्रक्रिया से संबंधित बताया, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है। डीआरएल ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का रोगी सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, समस्या के समाधान तक व्यावसायिक आपूर्ति में देरी होगी, जो अब अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में ही दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। इस खबर के बाद गुरुवार को बीएसई पर डीआरएल के शेयर 5.85 प्रतिशत गिर गए।

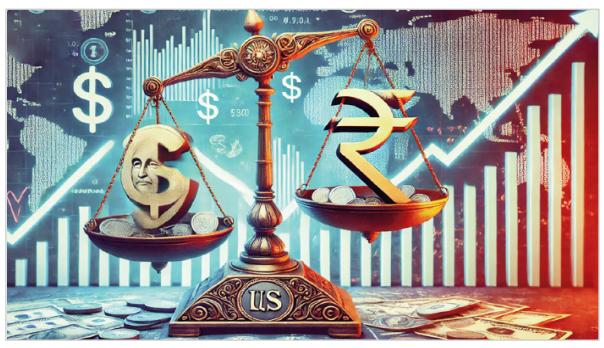
रुपया तेजी के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय 15 पैसे की तेजी के साथ ही 95.32 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह रुपया शुरुआती कारोबार में रुपया 15 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.32 पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू मुद्रा को बल मिला।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली और पश्चिम एशिया में तनाव से जुड़ी अनिश्चितताओं का स्थानीय मुद्रा पर दबाव रहा, जबकि घरेलू शेयर बाजारों में दिन की मजबूत शुरुआत से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 95.27 पर खुला।

बाद में 95.32 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 15 पैसे की बढ़त दिखात है। रुपया गुरुवार को एक पैसे की



बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.47 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.25 फीसदी की गिरावट के साथ 100.64 पर रहा।

मोबाइल, ईवी और मेडिकल डिवाइस के घटेंगे दाम

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर हटाई कस्टम ड्यूटी

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जारी तीन आधिकारिक आदेशों के तहत ऑटोमोटिव, चिकित्सा और औद्योगिक उपकरणों के लिए डिस्प्ले असेंबली के पुर्जों, मोबाइल फोन के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल के पुर्जों और लीथियम आयन सेल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है। यह छूट 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी, जिससे पहले लगने वाला 7.5 फीसदी से 15 फीसदी तक का शुल्क समाप्त हो गया है। इस फैसले से ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी निर्माण और ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा।

रक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, खासकर ड्रोन, रोबोट और मानव रहित प्रणालियों के उत्पादन में, जो उन्नत डिस्प्ले और बैटरियों पर निर्भर करते हैं।

मोटापा घटाने वाली जीएलपी-1 दवाओं की बिक्री में पहली मासिक गिरावट

बाजार में ठहराव के संकेत, लेकिन सालाना वृद्धि दर में जबरदस्त उछाल जारी

नई दिल्ली ।

भारत में मोटापा कम करने वाली जीएलपी-1 दवाओं की बिक्री में जून महीने में पहली बार मासिक गिरावट दर्ज की गई है। नोवो नॉर्डिस्क की सेमाग्लूटाइड दवा का पेटेंट खत्म होने और सस्ते जेनेरिक विकल्पों के बाजार में आने के बाद हुई शुरुआती तेजी अब धीमी पड़ती दिख रही है। हेल्थकेयर रिसर्च फर्म फार्मारैक के अनुसार मई के रिकॉर्ड 236 करोड़ रुपए से घटकर जून में इन दवाओं की बिक्री 227 करोड़ रुपए रह गई। सेमाग्लूटाइड का पेटेंट समाप्त होने के बाद मार्च के 180 करोड़ रुपए के बाजार ने अप्रैल में 218 करोड़ रुपए और मई में 236 करोड़ रुपए का उछाल देखा था। जून में सर्वाधिक बिकने वाली माउंजारो (टिर्जेपेटाइड) की बिक्री भी 136 करोड़ रुपए से घटकर 130 करोड़ रुपए हो गई, जबकि सेमाग्लूटाइड आधारित दवाओं की बिक्री 93 करोड़ रुपए से घटकर 91 करोड़ रुपए दर्ज की गई। हालांकि, सालाना आधार पर इस बाजार में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। पिछले वर्ष जून की तुलना में इस जून में जीएलपी-1 दवाओं की मासिक बिक्री लगभग तीन गुना बढ़ी है, और वार्षिक कारोबार 2,055 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 238 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब बाजार की आगे की वृद्धि केवल सस्ती दवाओं पर नहीं, बल्कि अधिक मरीजों तक पहुंच, लंबे समय तक इलाज जारी रखने और डॉक्टरों का विश्वास बनाए रखने पर निर्भर करेगी। फार्मारैक ने भारतीय दवा बाजार की कुल वृद्धि दर का अनुमान 2026 के लिए 11.3 प्रतिशत तक बढ़ाया है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 827, निफ्टी 244 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। इसी कारण आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 827.57 अंक बढ़कर 77,569.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 244.10 अंक बढ़कर 24,206.90 अंक पर पहुंच गया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। आज की इस जोरदार रैली में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने सबसे अधिक तेजी दर्ज करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी के शेयरों में आई इस बढ़त ने बाजार को ऊपर खींचने में मदद की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सर्वाधिक 2.37 फीसदी की तेजी आई, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा, बीईएल, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे दिग्गज शेयरों में भी उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में खरीदारी की भावना प्रबल दिखी। हालांकि, इस सकारात्मक माहौल के बावजूद कुछ शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जिनमें इटरनल, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ट्रेंट और आईटीसी शामिल रहे। निफ्टी के व्यापक आधार वाले शेयरों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस



कंपनी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की, जो वित्तीय सेवा क्षेत्र में मजबूत रुझान का संकेत है। व्यापक बाजार में भी निवेशकों का उत्साह बना रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.4 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.55 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। यह दिखाता है कि छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे यहां निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। सेक्टर-वार प्रदर्शन पर गौर करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई, जिसने दिन के कारोबार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूती साबित की। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बाजार को आवश्यक समर्थन प्रदान किया। दूसरी ओर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जो दिन के दौरान कमजोर रहा और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। कुल मिलाकर, भारतीय शेयर बाजार ने आज एक मजबूत और सकारात्मक सत्र का समापन किया, जिससे आने वाले दिनों के लिए भी आशावादी माहौल बना हुआ है।

ब्रिटिश कारों के लिए भारत में खुला रियायती आयात का रास्ता

15 जुलाई से लागू होगी कोटा-आधारित शुल्क व्यवस्था

नई दिल्ली ।

भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क पर वाहनों के आयात के लिए आधिकारिक प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। यह व्यवस्था 15 जुलाई से प्रभावी होगी, जिसके तहत ब्रिटिश-निर्मित वाहनों को कोटा-आधारित शुल्क रियायतों का लाभ मिलेगा। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत रियायती दरों पर वाहनों के आयात की प्रक्रिया अधिसूचित की है, जो 15 जुलाई से प्रभावी होगी। व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के अंतर्गत, भारत पारंपरिक इंजन वाले यात्री वाहनों पर सीमा शुल्क को मौजूदा लगभग 110 फीसदी से घटाकर अंतिम रूप से 10 फीसदी करेगा। अगले 15 वर्षों में ब्रिटेन से कुल 3.78 लाख ऐसी इकाइयां रियायती शुल्क पर आयात की जा सकेंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 9 जुलाई को अधिसूचना जारी कर बताया कि आयातकों को मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, और केवल ब्रिटेन में निर्मित वाहनों के मूल उपकरण विनिर्माता या उनके अधिकृत डीलर ही पात्र होंगे। इन आयातों के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती शुल्क का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पहले वर्ष में विभिन्न श्रेणियों की कुल 20,000 यात्री कारों पर सीमा शुल्क 110 फीसदी से घटाकर 30 या 66 से 50 फीसदी किया जाएगा। हालांकि, 40,000 ब्रिटिश पाउंड से कम कीमत वाले वाहनों के लिए भारत ने अपना बाजार नहीं खोला है, जिससे घरेलू जन बाजार और इलेक्ट्रिक वाहन खंड को संरक्षण मिलेगा।

इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित कारों पर पहले पांच वर्षों तक कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन छठे वर्ष से उच्च मूल्य वाले मॉडल पर रियायती शुल्क लागू होंगे।

एचएफसीएल को 495 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय डेटा सेंटर ठेका

नई दिल्ली ।



घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माता एचएफसीएल को एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर कंपनी से 495.80 करोड़ रुपये (लगभग 51.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का एक बड़ा निर्यात ठेका मिला है। यह ठेका ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित डेटा सेंटर संपर्क समाधानों की आपूर्ति के लिए है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को इसकी सूचना दी। एचएफसीएल ने बताया कि इस महत्वपूर्ण ठेके को दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। यह ऑर्डर कंपनी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी इकाई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि एचएफसीएल के हाल ही में ऑप्टीक्यू एआई डेटा सेंटर समाधान खंड की शुरुआत के बाद आई है, जो वैश्विक डेटा सेंटर बाजार में उसकी बढ़ती विशेषज्ञता और क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह ठेका कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक विस्तार का प्रतीक है, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी।

2000 के नोट अभी भी वैध,जानें बदलने के तीन आसान तरीके

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर आम जनता के बीच बनी किसी भी आशंका को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि ये गुलाबी नोट आज भी लीगल टेंडर (कानूनी रूप से वैध) हैं। आरबीआई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह ताजा जानकारी साझा की है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास अभी भी ये नोट मौजूद हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। तब बाजार में 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट थे। अप्रैल 2026 के अंत तक आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब सिर्फ 5,451 करोड़ रुपये के नोट ही बचे हैं, जिसका अर्थ है कि देश के 98.47 फीसदी नोट सफलतापूर्वक बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। यह दर्शाता है कि अब बेहद कम नोट ही लोगों के पास हैं। यदि आपके पास अभी भी 2000 के नोट हैं, तो आप इन्हें आसानी से बदल या जमा कर सकते हैं। इसके लिए तीन मुख्य तरीके ह- 1. आरबीआई कार्यालयों में- देश भर में मौजूद आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिसों में जाकर नोटों के बदले दूसरे वैध नोट (जैसे 500, 200) तुरंत प्राप्त करें। 2. सीधे खाते में जमा- इन्हीं आरबीआई कार्यालयों में एक फॉर्म भरकर नोटों की राशि सीधे अपने बैंक खाते (बचत या चालू) में ट्रांसफर करवाएं।

3. इंडिया पोस्ट के जरिए- यदि आप आरबीआई कार्यालय से दूर हैं।

टीसीएस की कमाई उम्मीद से बेहतर, एआई और डील्स ने भरा जोश, ब्रोकरेज हुए खुश!

पहली तिमाही में 9.5 अरब डॉलर की नई डील्स, एआई का सालाना राजस्व रन रेट 2.6 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। मजबूत डील बुकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि और स्थिर राजस्व प्रदर्शन ने बाजार का ध्यान खींचा है, जबकि वेतन वृद्धि और रणनीतिक निवेश के चलते मार्जिन पर अस्थायी दबाव देखा गया। विश्लेषकों ने कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी रुख बनाए रखा है, जिससे शुक्रवार सुबह कारोबार में टीसीएस के शेयर में 2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

टीसीएस ने जून तिमाही में 7.62 अरब डॉलर का डॉलर राजस्व दर्ज किया, जो स्थिर मुद्रा में पिछली तिमाही से 0.4 फीसदी और सालाना आधार पर 3.2 फीसदी अधिक है, जो बाजार अनुमानों से थोड़ा बेहतर है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा लगभग 13,400 करोड़ रुपये रहा, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप था। इस तिमाही की सबसे बड़ी उपलब्धि 9.5 अरब डॉलर की नई डील्स रहीं, जो आगामी तिमाहियों के लिए मजबूत ऑर्डर बुक का संकेत देती हैं। एआई कारोबार भी तेजी से गति पकड़ रहा है, जिसका वार्षिक राजस्व रन रेट 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 13.6 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने इस अवधि में 9,279 नए कर्मचारियों की भर्ती की और शेयरधारकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा भी की।

हालांकि, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और एआई, सेल्स तथा नई साझेदारियों में निरंतर निवेश के कारण कंपनी का ए बिट मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 1.3 प्रतिशत अंक घटकर 24 फीसदी रह गया, जिससे मार्जिन पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बावजूद इसके, प्रमुख ब्रोकरेज हाउसों ने टीसीएस पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। एक रे टिंग एजेंसी ने बाय रेटिंग के साथ 12 महीनों के लिए 3,000 रुपये का लक्ष्य दिया है, उसका मानना है कि कंपनी के लिए अब आगे का रास्ता बेहतर दिख रहा है और हालिया गिरावट के बाद मौजूदा भाव पर शेयर आकर्षक है।

भविष्य की बात करें तो, मजबूत डील पाइपलाइन और एआई कारोबार में सतत विस्तार टीसीएस के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

निवेशकों की दुविधा स्टॉक एसआईपी या म्यूचुअल फंड एसआईपी, कौन है बेहतर?

सही विकल्प का चुनाव करने के लिए दोनों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को समझना बेहद जरूरी

नई दिल्ली ।

लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का एक सबसे लोकप्रिय और प्रभावी तरीका बन चुके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) को लेकर निवेशकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है- बेहतर रिटर्न के लिए सीधे शेयरों में एसआईपी (स्टाक एसआईपी) करना उचित है या म्युचुअल फंड एसआईपी का चुनाव करना चाहिए?

वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करने के लिए दोनों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को समझना बेहद जरूरी है। स्टॉक स्टाक एसआईपी में निवेशक हर महीने एक निर्धारित राशि से सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीदता है। इसमें शेयर का चुनाव पूरी तरह निवेशक पर निर्भर करता है, जिससे इसमें उच्च रिटर्न की संभावना तो होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है और निवेशक को कंपनियों व बाजार पर लगातार नजर रखनी पड़ती है।

इसके विपरीत, म्युचुअल फंड एसआईपी में निवेशक हर महीने एक तय रकम म्युचुअल फंड स्कीम में निवेश करता है। यहां निवेश से जुड़े सभी फैसले पेशेवर फंड मैनेजर करते हैं, जो विभिन्न शेयरों और अन्य एसेट्स में पैसा लगाते हैं। इससे निवेश में विविधता आती है और निवेशक को शेयर चुनने या पोर्टफोलियो संभालने की चिंता नहीं करनी पड़ती।

वैल्यूमैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज के एक को-फाउंडर के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की सही पहचान और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने पर स्टॉक एसआईपी निश्चित रूप से म्युचुअल फंड एसआईपी से बेहतर रिटर्न दे सकता है।

हालांकि, उनका मानना है कि ऐसी कंपनियों की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है और गलत शेयरों के चुनाव की संभावना सफल होने से कहीं ज्यादा होती है।

जैन के मुताबिक, सीधे शेयरों में निवेश के लिए कंपनी के कारोबार, उसके मूल्यांकन और बाजार की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना अनिवार्य है।

इसके विपरीत ज्यादातर निवेशकों के लिए म्युचुअल फंड एसआईपी एक बेहतर विकल्प साबित होता है। इसमें पेशेवर फंड मैनेजर बाजार की स्थितियों के अनुसार पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं और निवेश को कर-कुशल बनाने का प्रयास करते हैं।

भारत ने चीनी सीमलेस ट्यूब पर डंपिंग रोधी शुल्क 2027 तक बढ़ाया

घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण को प्राथमिकता

नई दिल्ली ।

घरेलू विनिर्माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने चीन से आयातित कुछ सीमलेस ट्यूब और पाइप पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क को 27 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। यह शुल्क, जो लोहे, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात के सीमलेस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल पर पहली बार 28 अक्टूबर, 2021 को लगाया गया था, वर्तमान में 961.33 डॉलर से 1,610.67 डॉलर प्रति टन के बीच है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसे प्रभावी बनाए रखने की पुष्टि की है।

इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने



मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से निर्यात किए जाने वाले 'नॉर्मल ब्यूटानॉल' (जो रसायन, पेंट और चिपकने वाले पदार्थों में उपयोग होता है) के आयात पर भी पांच वर्ष के लिए डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की घोषणा की है।

तब बाढ़ में भी नहीं डूबेंगे धान के पौधे!



तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। अब जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीनों का पता लगाया है जिनके जरिए चावल के पौधे का विकास इस तेजी से बढ़ाया जा सकता है कि वह पानी में डूबे ही नहीं।

भारत में चावल उगाने वाले किसान जहां बरसात के लिए तरसते हैं, वहीं उससे बहुत डरते भी हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं, क्या बरसात ठीक वक्त पर आएगी, ज़्यादा तेज और लंबी तो नहीं होगी, कितनी बार फसल बरसात की वजह से खराब हो जाती है और हज़ारों किसानों के लिए भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों में भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।

अक्सर यह देखा गया है कि तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। खेतों मे बढ़ता हुआ जलस्तर चावल के पौधों के लिए सामान?यत- अच्छा ही रहता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि पौधे के उपरी हिस्से हवा के संपर्क में बने रहें। हालांकि मानसूनी इलाकों में बरसात और बाढ की वजह से चावल के खेतों में पानी इतना ज?यादा भर जाता है कि धान के पौधे बिल्कुल डूब जाते हैं तथा इससे वे सड़ने लगते हैं और मर भी जाते हैं।

गौरतलब है कि गहरे पानी में उगनेवाले चावल की प्रजाति को जलजमाव से कोई समस्या नहीं होती। पानी के साथ-साथ उसके तने वाले डंठल भी बढ़ते जाते हैं।



जापान के नागोया विश्वविद्यालय के मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

गहरे पानी में उगने वाले चावल के पौधे, पानी की गहराई से ऊपर बने रहने के लिए, एक मीटर तक बढ़ सकते हैं। वे हवा के संपर्क में बने रहने के लिए ऐसा करते है। वे अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन उसके जरिए पौधा पानी की सतह से उपर पहुंच सकता है और ऑक्सीजन पा सकता है। यह कुछ ऐसा ही है कि जब आप गोताखोरी कर रहे होते हैं, तो पानी से ऊपर निकली एक नली से सांस लेते हैं।

बरसात के समय ऐसे चावल के तने 25 सेंटीमीटर प्रतिदिन की एक अनोखी गति से बढ़ सकते हैं। अशिकारी और उनकी टीम ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस चावल के जीनों से यह समझने की कोशिश की कि चावल बरसात के वक्त अपने विकास को किस तरह नियंत्रित करता है। अध्ययनों से अब तक जितना पता चला है वह यह है कि एक गैसीय विकास-हॉर्मोन एथीलिन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसाकि नीदरलैंड के उएतरेश्त विश्वविद्यालय के रेंस वोएसेनेक बताते हैं-

जब पौधा पूरी तरह पानी में डूब जाता है तब यह गैस ठीक तरह से मुक्त नहीं हो पाती। यू कहें कि वह पौधे में ही कैद हो जाती है। यानी पौधे में एथिलिन की मत्रा बढ़ने लगती है। यह पौधे के लिए संकेत है कि वह पानी में डूब रहा है और उसे कुछ करना है।

जापानी विशेषज्ञों ने पता लगाने की कोशिश की कि कौन से जीन इस स्थिति में सक्रिय होते हैं। उन्होने ऐसे जीन पाए जिनको वे गोताखोरी में इस्तेमाल होनेवाली नली के अनुरूप स्नोर्कल जीन कहते हैं। ये जीन तभी सक्रिय होते हैं जब पौधे के तने में एथिलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। वे पौधे के विकास को तेज करने वाले दूसरे तत्वों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

हमने क्रॉमोसोम 1,3 और 12 पर यह तथाकथित नलिका जीन पाए। उन्हें यदि सामान्य चावल के पौधों में भी मिलाया जा सके, तो बरसात के वक्त सामान्य चावल के पौधे भी वही करेंगे जो गहरे पानी में उगने वाला चावल करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चावल की हर प्रजाति को गहरे पानी में उगने वाले चावल की प्रजाति बना सकते हैं।

यानी इन जीनों की मदद से चावल की उस फसल को बचाया जा सकता है जो पानी की अधिकता के प्रति बहुत संवेदनशील है। जहां अक्सर बाढ आती है वहां के किसानों की इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक और समस्या भी दूर हो सकती है - गहरे पानी में उगने वाला चावल बहुत ही कम फसल देता है, प्रति हेक्टेयर सिर्फ एक टन जो उपजाऊ क़िस्मों की तुलना में सिर्फ 20 फीसदी के बराबर है। नीदरलैंड के विशेषज्ञ रेंस वोएसेनेक बहुत ही आशावादी हैं-

विकास के लिए जिम्मेदार इन जीनों के बारे में पता चल जाने के बाद अब हम चावल की अलग-अलग प्रजातियों के बीच प्रकृतिक संवर्धन के जरिए, यानी वर्णसंकर के जरिए भी इन जीनों को उनके पौधे में डाल सकते हैं। इसके लिए किसी जीन तकनीक जरूरत ही नहीं हैं।

जापान के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर भी दिया है। उनके अध्ययनों से एक बार फिर पता चलता है कि पौधों के संवर्धन के लिए उनके जीनों में असामान्य गुणों की तालाश कितनी जरूरी है।

कुदरती खेती का एक अनूठा प्रयोग

भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रकृति की कृपा तथा हमारे किसानों कि आर्थिक मेहनत से हमारी भूमि सदा उपजाऊ रही है। प्राचीन समय में हमारी खेती प्राकृतिक संपदा व संसाधनों पर ही निर्भर थी और देश की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर पाती थी। जैसे-जैसे देश में शहरीकरण व औद्योगिकरण बढते गये , गांवों से लोग खेती को छोड़ शहरों की ओर आते गये। प्राकृतिक खेती पध्दति कम होती गई और रासायनिक खाद आदि का प्रयोग बढता गया। ज़मीन की उत्पादकता घटती गई और साथ ही किसान की आय भी। सन 1965 में भारत में हरित क्रांति आयी जिससे उपज तो बढी मगर रासायनिक उरवरक तथा अन्य उत्पादों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से मिटटी की उत्पादकता भी कम होती गयी।

यूरोप, अमरीका व एशिया में सन् 1940-50 के दकों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं पर बहुत प्रयोग किये गये। खेती कि ये विधायें भारत में सन 1980 के दशक से आगे बढी हैं। जैविक खेती की पद्धति में रासायनिक पध्दाथों का प्रयोग वर्जित है। प्राकृतिक खेती में केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं व संसाधनों का ही प्रयोग होता है। आधुनिक खेती या रासायनिक खेती प्रकृति के खिलाफ है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों से हमारे खेतों की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और जैव तत्त्व मर रहे हैं और वह बंजर हो जाती है। कुदरती खेती प्रकृति के साथ होती है। यद्यपि प्राकृतिक खेती की शुरूआत जापान के कृषि वैज्ञानिक फुकुओवा ने की है लेकिन हमारे यहां भी ऐसी खेती होती रही है। मंडला के बैगा आदिवासी बिना जुताई की खेती करते हैं जिसे झूम खेती कहते हैं।

भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले के एक फार्म मे लगभग पिछले 25 वर्षों से प्राक्रतिक खेती, जिसे कुदरती खेती भी कहते है, हो रही है। करीब 12 एकड़ के इस फार्म में सिर्फ 1 एकड़ में खेती की जा रही है। यहां बिना जुताई (नो टिलिग) और रासायनिक खाद के खेती की जा रही है। बीजों को मिट्टी की गोली बनाकर बिखेर दिया जाता है और वे उग आते हैं। यह सिर्फ खेती की एक पद्धति भर नहीं है बल्कि जीवनशैली है। यहां का अनाज, फल पानी और हवा शुध्द है। यहा कुआं है, जिसमें पर्याप्त पानी है। बिना जुताई के खेती मुश्किल है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। पहली बार सुनने पर विश?वास नहीं होता लेकिन देखने के बाद सभी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। दरअसल, इस पर्यावरणीय पद्धति में मिट्टी की उर्वरता उत्तारोतर बढ़ती जाती है।

बाकी के 11 एकड़ में सुबबूल (आस्टेलियन अगेसिया) का जंगल है। सुबबूल एक चारे की प्रजाति है। इस जंगल से मवेशियों का चारा और लकड़ियां मिल जाती हैं। लकड़ियों की टाल है, जहां से जलाऊ लकड़ी बिकती हैं, जो फार्म की आय का मुख्य स्रोत है। एक एकड़ जंगल से हर वर्ष करीब ढाई लाख रूपये की लकड़ी बेच लेते हैं।

गेहूं के खेतों में हवा के साथ गेहूं के हरे पौधे लहलहाते हैं। खेत में फलदार और अन्य जंगली पेड़ हैं जिनके नीचे गेहूं की फसल होती है। आम तौर पर खेतों में पेड़ नहीं होते हैं लेकिन यहां अमरूद, नीबू और बबूल के पेड़ हैं जिन के कारण खेतों में गहराई तक जड़ों का जाल बुना रहता है। इससे भी जमीन ताकतवर बनती जाती है। अनाज और फसलों के पौधे पेड़ों की छाया तले अच्छे होते हैं। छाया का असर जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर करता है। चूंकि यहां जमीन की उर्वरता अधिक है, इसलिए पेड़ों की छाया का फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।



इन खेतों में पुआल, नरवाई, चारा, तिनका व छोटी-छोटी टहनियों को पड़ा रहने देते हैं, जो सड़कर जैव खाद बनाती हैं। खेत में तमाम छोटी-बड़ी वनस्पतियों के साथ जैव विविधताएं आती -जाती रहती हैं। और हर मौसम में जमीन ताकतवर होती जाती है। इस जमीन में पौधे भी स्वस्थ और ताकतवर होते हैं जिन्हें जल्द बीमारी नहीं घेरती।

यहां जमीन को हमेशा ढककर रखा जाता है। यह ढकाव हरा या सूखा किसी भी तरह से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस ढकाव के नीचे अनगिनत जीवाणु, केंचुए और कीड़े-मकोड़े रहते हैं और उनके ऊपर-नीचे आते-जाते रहने से जमीन पोली और हवादार व उपजाऊ बनती है।

आमतौर पर किसान अपने खेतों से अतिरिक्त पानी को नालियों से बाहर निकाल देते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाता। बारिश में कितना ही पानी गिरे, वह खेत के बाहर नहीं जाता। खेतों में जो खरपतवार, ग्रीन कवर या पेड़ होते हैं, वे पानी को सोखते हैं। इससे एक ओर खेतों में नमी बनी रहती है, दूसरी ओर वह पानी वाश?पीकृत होकर बादल बनता है और बारिश में पुन् बरसता है। इसके विपरीत, जब जमीन की जुताई की जाती है और उसमें पानी दिया जाता है तो खेत में कीचड़ हो जाती है। बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता और तेजी से बहता है। पानी के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस तरह हम मिट्टी की उपजाऊ परत को बर्बाद कर रहे हैं और भूजल का पुनर्भरण भी नहीं कर पा रहे हैं। साल दर साल भूजल नीचे चला जा रहा है।







यहां खेती भोजन की जरूरत के हिसाब से होती हैं, बाजार के हिसाब से नहीं। जरूरत एक एकड़ से ही पूरी हो जाती है। यहां से अनाज, फल और सब्जियां मिलती हैं, जो परिवार की जरूरत पूरी कर देती हैं। जाड़े मे गेहूं, गर्मी में मक्का व मूंग और बारिश में धान की फसल ली जाती है। कुदरती खेती में भूख मिटाने के साथ समस्त जीव-जगत के पालन का विचार है। इससे मिट्टी-पानी का संरक्षण होता हैं। इसे ऋषि खेती भी कहते हैं क्योंकि ऋषि मुनि कंद-मूल, फल और दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, बहुत कम जमीन पर मोटे अनाजों को उपजाते थे। वे धरती को अपनी मां के समान मानते थे, उससे उतना ही लेते थे जितनी जरूरत थी। अत- कुदरती खेती का यह प्रयोग सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

13 चौके, 23 छक्के, 55 गेंद, नाबाद 206 रन



अंग्रेज बल्लेबाज का टी20 में दोहरा शतक, टीम ने खड़ा किया 417 रन का स्कोर

नई दिल्ली। भारतीय टीम इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इसी बीच इंग्लैंड में ही एक क्लब टी20 मैच में डम्बलटन क्रिकेट क्लब की टीम ने 417 रन का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। प्रीमियर वन टॉप टियर डिवीजन के टी20 मैच में यह रिकॉर्ड बना। इस मैच में डम्बलटन क्लब के बल्लेबाज इवान गेग ने दोहरा शतक भी लगाया। उन्होंने 55 गेंद में 206 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 23 छक्के लगाए।



इस टूर्नामेंट में डम्बलटन क्रिकेट क्लब की टीम ने हेदरली एंड रेडिंग्स क्लब के खिलाफ मुकाबले में 417 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस दौरान 22 चौके और 47 छक्के डम्बलटन की पारी में लगे। टीम की ओर से सिर्फ चौके छक्कों से ही 370 रन बने। इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए हेदरली की टीम 188 रन से मैच हार गई और 229 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में कुल तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाए। डम्बलटन की तरफ से एक दोहरा शतक और एक शतक लगा। ओपनर इवान गेग ने 206 रन की पारी खेली। वहीं उनके साथी डेन हॉलैंड ने 37 गेंद में 122 रन की पारी खेली। वहीं 418 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हेदरली एंड रेडिंग्स की टीम की तरफ से हैरी ब्लूमफील्ड ने भी 109 रन की पारी खेली। उन्होंने 48 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और 12 छक्के लगाए।



- **टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर–** टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो जिम्बाब्वे के नाम सर्वाधिक 344/4 रन का विशाल स्कोर दर्ज है। जिम्बाब्वे ने जाम्बिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड स्कोर 2024 में बनाया था। जबकि टी20 क्रिकेट में एक टीम के सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बड़ौदा का है। बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ 2024 में 5 विकेट पर 349 रन बनाए थे। टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात करें तो यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है जिसने 304 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में बनाए थे।

फ्रांस ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

एम्बाप्पे ने की मेसी की बराबरी

नई दिल्ली। बोस्टन के जिलेट स्टेडियम में खेले गए 2026 फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले के गोलों की बदौलत फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से करारी शिकस्त दी। फ्रांस लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। कतर में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था। एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में पहला गोल किया।



इसके ठीक छह मिनट बाद डेम्बेले ने दूसरा गोल करके फ्रांस की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले हाफ में एम्बाप्पे ने पेनल्टी को गोल में बदलने से चूक गए, लेकिन इससे उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे हाफ में एक शानदार गोल किया और फिर उस्मान डेम्बेले को असिस्ट भी किया। इस गोल के साथ, एम्बाप्पे आठ गोलों के साथ लियोनेल मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

इंग्लैंड से पहली बार टी20 सीरीज हारा भारत

7 साल बाद लगातार दो सीरीज हारे विश्व विजेता

नई दिल्ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार मैच हार रही है। इंग्लैंड ने शुक्रवार (10 जुलाई) को चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने पहली बार दो या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में भारत को हराया है।

भारत ने पिछले छह में से पांच सीरीज जीते हैं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। मार्च में लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से पहले आयरलैंड से 2 मैचों की टी20 सीरीज हारी। इससे पहले भारतीय टीम फरवरी 2019 में लगातार 2 टी20 सीरीज हारी थी। न्यूजीलैंड ने उसे 1-2 और ऑस्ट्रेलिया ने उसे 2-0 से हराया था। मौजूदा सीजन से पहले भारत ने अपनी पिछली 12 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में से 11 में जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।



इंग्लैंड से 2018 के बाद सीरीज हारी भारतीय टीम

भारतीय टीम 2018 में इंग्लैंड दौरे पर 2 सीरीज हारी थी। वनडे में में 2-1 और टेस्ट में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच खेली गई किसी भी प्रारूप की सीरीज भारतीय टीम नहीं हारी थी। वह 10 में से 8 सीरीज जीती थी। इंग्लैंड में खेली गई पिछली 2 टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रहीं।

इंग्लैंड की दूसरी बड़ी जीत– भारत ने चौथे टी20 में 37 गेंद रहते 9 विकेट से जीत हासिल की। 150 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए यह इंग्लैंड की विकेट के हिसाब से संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में 192 रनों के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल किया था।

इंग्लैंड ने नौ विकेट से हराया

3-0 से बनाई अजेय बढ़त

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में हुआ। इंग्लैंड ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत को 9 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर



पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर मुकाबला जीत लिया। फिल साल्ट ने 59 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 79 रन बनाकर शानदार अर्धशतक जड़े। इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली है और 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है।



श्रेयस अय्यर ने तोड़ा रोहित शर्मा और एमएस धोनी का रिकॉर्ड

- **ब्रिस्टल में टॉस जीतते ही किया कमाल**

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से टॉस जीता। बतौर भारतीय कप्तान उन्होंने लगातार अपना छठा टॉस जीता और रोहित शर्मा व एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में भले अभी तक पहला मैच नहीं जीता है लेकिन वह एक भी टॉस अभी तक नहीं हारे हैं। श्रेयस अय्यर ने इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भी दोनों मैचों में टॉस जीता था। वह मौजूदा इंग्लैंड सीरीज में भी पहले चारों मैच में टॉस जीते हैं। उन्होंने बतौर कप्तान लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में विराट कोहली (6) की बराबरी की है। वह अब लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय कप्तान बने हैं।

लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान

- 7 : एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)
- 6 : विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)
- 6* : श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)
- 5 : रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)
- 5 : एमएस धोनी (सितंबर 2007)

वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में अब तक का प्रदर्शन

5 छक्के, 27 गेंद, 42 रन

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज खास नहीं रहा है। इंग्लैंड में खेली पहली तीन पारियों में लगातार वह फेल ही साबित हुए हैं। उन्होंने पहली तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन ही बनाए हैं। अभी तक लगातार उनकी आईपीएल वाली कमजोरी ही इंग्लैंड में उजागर हुई है। वह तीनों मुकाबलों में शॉर्ट बॉल के सामने दिक्कत में दिखे हैं। पिछली दोनों पारियों में वह शॉर्ट पिच डिलीवरी पर ही आउट हुए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड सीरीज में अभी तक तीन पारियों में 42 रन ही बनाए हैं। उन्होंने 27 गेंद का सामना किया है जिसमें 5 छक्के और सिर्फ एक चौका उनके बल्ले से निकला है। मगर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत शॉर्ट बॉल की समस्या नहीं दूर हो रही है। जोफ्रा आर्चर ने लगातार दूसरी बार वैभव का विकेट झटका है।

उन्होंने ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में 10 गेंद पर 15 रन ही बनाए हैं। इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए मैनचेस्टर में उन्होंने 12 गेंद पर 14 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी में नॉटिंघम में वह 13 रन ही बना पाए थे। नॉटिंघम के बाद ब्रिस्टल में भी वह आर्चर का शिकार बने हैं। आर्चर के खिलाफ वैभव ने 3 पारियों में 13 गेंद पर सिर्फ 18 रन ही बनाए हैं और दो बार उनका शिकार भी वह बने हैं।



वैभव सूर्यवंशी की जगह पर मंडराया खतरा?

भारतीय टीम ने तीन महीने पहले विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन को बाहर करते हुए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह दी थी। अब वैभव ने पहली तीनों पारियों में निराश किया है। उनके अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं।

वैभव को जितनी तेजी से टीम में लाने की मांग उठ रही थी। उतनी तेजी से ही अब उनकी खामियां सामने आ रही हैं। इसी कारण सीरीज के आखिरी मुकाबले में अब उनकी जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने पहली तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बनाए हैं। उनका इंटरनेशनल डेब्यू खास नहीं रहा है। अब आखिरी टी20 में उनकी जगह संजू सैमसन की एंट्री होती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

भारत ने गंवाई यूथ वनडे सीरीज

रोमांचक मैच में 1 विकेट से जीता श्रीलंका, अंतिम 10 ओवर में ठोके 76 रन

नई दिल्ली। श्रीलंका की अंडर-19 टीम ने हम्बनटोटा में खेले गए तीसरे यूथ वनडे में भारतीय टीम को एक विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने 2-1 से यूथ वनडे सीरीज अपने नाम की। हम्बनटोटा के महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

इंडिया -19 टीम ने वीके विनीत के शतक की मदद से 50 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका -19 ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 291 रन बनाकर मैच और सीरीज अपने नाम की। चार जून 2026 को इसी मैदान पर खेले गए पहले यूथ वनडे इंटरनेशनल को इंडिया -19 ने 4 विकेट से जीता था, लेकिन छह जुलाई को हुए दूसरे वनडे



इंटरनेशनल में उसे आठ विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी।

तीसरे यूथ वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो श्रीलंका -19 का 40 ओवर में स्कोर आठ विकेट पर 215 रन था। श्रीलंका -19 को 10 ओवर में 76 रन बनाने थे और उसके सिर्फ दो विकेट गिरना शेष थे। इसके बाद चमिका हीनतिगाला और गिम्हन मेंडिस ने नौवें विकेट के लिए 47 गेंद में 61 रन की साझेदारी की। गिम्हन मेंडिस 22 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए।

चमिका हीनतिगाला सात चौके और दो छक्के की मदद से 68 गेंद में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका -19 की ओर से सेनूजा वेकुनागोडा ने भी अर्धशतक लगाया। सेनूजा वेकुनागोडा ने 10 चौके और एक छक्के की मदद से 59 गेंद में 67 रन की पारी खेली। इंडिया -19 की ओर से अनमोलजीत सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे।

अनमोलजीत सिंह ने 8 ओवर में 42 रन देकर चार विकेट लिए। शाविन विनोद 10 ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे। मोहित उल्वा ने भी दो विकेट लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने नौ ओवर में 66 रन दे डाले।

30 पदकों का बड़ा झटका

कुश्ती-बैडमिंटन समेत 6 खेलों के हटने से भारत की मेडल उम्मीदों पर संकट

नई दिल्ली। बर्मिंघम 2022 के खेलों में इन हटाए गए खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 30 पदक (13 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य) जीते थे, जो भारत के पूरे 61 पदकों का लगभग आधा हिस्सा है। यह नुकसान भारत के लिए नया नहीं है, बल्कि पिछले कई संस्करणों का इतिहास बताता है कि इन खेलों को हटाने से भारत को हमेशा बड़ा आर्थिक व खेल-कूद का नुकसान उठाना पड़ा है।



- **कुश्ती :** बर्मिंघम 2022 में भारत ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित 12 पदक हासिल किए थे। अगर पीछे देखें, तो गोल्ड कोस्ट 2018 खेलों में भी भारतीय पहलवानों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक देश की झोली में डाले थे।
- **बैडमिंटन :** साल 2022 में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग की जोड़ी के दम पर भारत ने 3 स्वर्ण समेत 6 पदक हासिल किए। इससे पहले 2018 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण (मिक्सड टीम और सायना नेहवाल), 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते थे। 2014 में भी बैडमिंटन से 1 स्वर्ण (पारुपल्ली कश्यप), 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक आए थे।
- **टेबल टेनिस :** बर्मिंघम 2022 में टेबिल टेनिस में अचंत शरद कमल के नेतृत्व में पैरा-इवेंट्स को मिलाकर 4 स्वर्ण समेत 7 पदक आए।
- **हॉकी और स्क्वैश :** बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, जबकि हॉकी में 2 पदक (1 रजत, 1 कांस्य) और स्क्वैश में 2 कांस्य पदक भारत के नाम रहे।



मैंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं आने दिया

अभिनेता और फिल्ममेकर कुणाल खेमू इन दिनों अपने नए रियलिटी शो 'अलायंस' को लेकर चर्चा में हैं। कुणाल ने हाल ही में उस सवाल का जवाब दिया, जो अक्सर उनसे पूछा जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का हिस्सा बनने के बाद क्या उन्हें कभी किसी तरह का दबाव या उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ? इस पर कुणाल ने कहा कि उन्होंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं आने दिया। बातचीत में सवाल का जवाब देते हुए कुणाल ने कहा, ''नहीं, मेरे लिए मेरी कला और मेरे भीतर का कलाकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही मेरे लिए सबसे अहम है। सच कहूं तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं कि मैं शर्मिला टैगोर का दामाद हूं।'' अगर मैं यह कहूं कि मैं इस बारे में सोचता हूं या इससे बचने की कोशिश करता हूं, तो यह झूठ होगा। यह बात मेरे दिमाग में रहती ही नहीं है।'' अभिनेता ने आगे कहा, ''मेरी क्रिएटिव जर्नी हमेशा एक्टिंग और फिल्ममेकिंग के प्रति मेरे पैशन से प्रेरित रही है। मैंने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया कि मैं किस परिवार का हिस्सा हूं। किसी कलाकार की असली पहचान उसके काम से बनती है, न कि उसके पारिवारिक रिश्तों से।'' बता दें कि कुणाल खेमू ने अभिनेत्री सोहा अली खान से 25 जनवरी 2015 को शादी की थी। सोहा अली खान, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की बेटी हैं।



कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ काम करने का काजल ने शेयर किया अनुभव

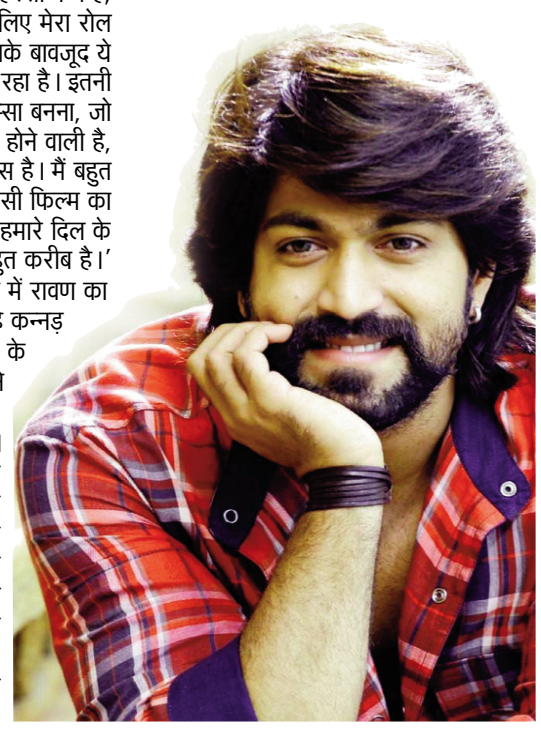
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में दिखेंगे। जहां फैंस इस बड़ी स्टारकास्ट को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं काजल ने खुलासा किया है कि फिल्म के पहले पार्ट में उनका रोल काफी छोटा है।

पहले पार्ट में लिमिटेड है काजल का रोल

हाल ही में इंटरव्यू में काजल ने बताया कि पहले पार्ट में मंदोदरी का रोल ज्यादा नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि कहानी का बड़ा हिस्सा लंका से पहले का है, इसलिए उनके किरदार को शुरुआती हिस्से में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। काजल ने कहा, 'हमने अभी सिर्फ पार्ट 1 की शूटिंग की है और जाहिर है उसमें लंका का हिस्सा कम है, और मैं मंदोदरी हूं। इसलिए मेरा रोल बहुत लिमिटेड है। इसके बावजूद ये अनुभव बहुत शानदार रहा है। इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना, जो एक वर्ल्ड फिल्म होने वाली है, बहुत खास एहसास है। मैं बहुत आभारी हूं कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं, जो हमारे दिल के बहुत करीब है।'

काजल ने इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उनके काम की फैन रही हैं और उनके साथ काम करना शानदार रहा। उन्होंने कहा, 'वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं हमेशा से उनके काम को पसंद करती आई हूं और इस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो इस फिल्म को लेकर बहुत इन्वॉल्व हैं। वो बेहद प्रोफेशनल हैं और निश्चित तौर पर बहुत टैलेंटेड हैं।'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। अब तक मेकर्स ने फिल्म की सिर्फ एक झलक दिखाई है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आए। साथ ही रवि दुबे (लक्ष्मण), साई पल्लवी (सीता) और अयोध्या की भव्य दुनिया की झलक भी देखने को मिली।





मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी नहीं होगी 'हैवान'

सैफ अली खान और अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म 'हैवान' में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर सैफ ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'हैवान' उनकी 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी बिल्कुल नहीं है। एक खबर के अनुसार, सैफ ने बताया कि 'हैवान' में अक्षय कुमार एक खतरनाक विलेन के रोल में नजर आएंगे। सैफ उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। सैफ ने अक्षय को अपने बड़े भाई जैसा बताया है। उनका कहना है कि दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती है, दोनों एक-दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। भले ही फिल्म 'हैवान' की कहानी बहुत गंभीर है, लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय और सैफ कैमरे के पीछे खूब मजाक-मस्ती करते थे। उनकी इन शरारतों को देखकर निर्देशक प्रियदर्शन उन्हें अक्सर बच्चों की तरह डांटते भी थे। 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी पिछली फिल्मों में दोनों ने दर्शकों को खूब हंसाया था। लेकिन सैफ ने साफ किया है कि 'हैवान' कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर कहानी पर आधारित है। आखिर में सैफ ने कहा कि अगर भविष्य में कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली, तो वह अक्षय के साथ फिर से कोई कॉमेडी फिल्म जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को 'हैवान' में इन दोनों का एक बिल्कुल अलग और रोमांचक अंदाज देखने को मिलेगा। 'हैवान' का निर्देशक प्रियदर्शन कर रहे हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म है। 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ नजर आएंगे।



जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है रणवीर सिंह की अगली फिल्म 'प्रलय'

'धुरंधर' की सफलता के बाद फैंस रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्ममेकर जय मेहता की जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है। साथ ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रलय' की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक सोर्स ने बताया, 'रणवीर 2026 के दूसरे हाफ में जय मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। फिल्म के बड़े पैमाने और जॉनर को देखते हुए इसके लिए जबरदस्त फिजिकल और इमोशनल तैयारी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जहां जय मेहता और उनकी टीम उन टेक्नीशियन्स के साथ मिलकर काम कर रही है जो पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिल्म की विशाल पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रलय' काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी और राइटिंग टीम स्क्रीनप्ले और फिल्म की बड़ी जॉम्बी दुनिया को बेहतर बनाने का काम जारी रखेगी।



महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए उम्मीद भरा दौर है

बीते दिन शुक्रवार को यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' रिलीज हुई, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी अहम भूमिकाओं में हैं। इसी के साथ हुमा कुरैशी अभिनीत 'बेबी डू डाई डू' ने भी दस्तक दी। दोनों फिल्मों के क्लैश पर हाल ही में हुमा कुरैशी ने चुप्पी तोड़ी।

फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरैशी ने एक मूक बधिर दिव्यांग का किरदार अदा किया है। इस भूमिका के लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। हाल ही में हुमा ने फिल्म पर बात की। हुमा ने कहा, 'मैं एक ऐसी महिला किलर का रोल कर रही हूं, जो सुन या बोल नहीं सकती। यह कोई कमी या कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में उसकी ताकत है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किलर हमेशा पुरुष ही होता है। महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए बढ़ते स्पेस के बारे में बात करते हुए हुमा कुरैशी ने कहा कि दर्शकों की बदलती उम्मीदों और अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की वजह से, मौजूदा समय महिलाओं के नेतृत्व वाली एक्शन फिल्मों के लिए एक उम्मीद भरा दौर है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रहने वाले हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। बातचीत के दौरान हुमा कुरैशी ने 'बेबी डू डाई डू' और 'अल्फा' के बॉक्स ऑफिस टकराव पर भी चुप्पी तोड़ी। हुमा ने दोनों महिला प्रधान फिल्मों के एक साथ आने का स्वागत किया। हुमा ने कहा, 'मैं 'अल्फा' को कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखती। मुझे लगता है कि हर तरह की फिल्में बनने और देखे जाने की गुंजाइश है। हमारी फिल्म इंडिपेंडेंटली बनी है। मैं यह भी नहीं देख रही कि उस वीकएंड और क्या रिलीज हो रहा है? बस अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहती हूं। दूसरी ओर, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां बॉक्स ऑफिस पर दो महिला-प्रधान फिल्में टकरा रही हैं। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां यह असलियत है।



आज हर वो शख्स क्रिएटर है, जिसके पास फोन है



पिछले दिनों अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स की भूमिका में तारीफें बटोरने वाली कंगना इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं रिएलिटी शो 'लॉकअप' को लेकर। उनकी 'क्वीन 2' को लेकर भी खबरें हैं है कि वो फिल्म पूरी हो चुकी है। अपनी भूमिकाओं में जान डाल देने वाली यह अभिनेत्री पॉलिटिशियन के रूप में भी धाकड़ हैं। हिमाचल की रहने वाली कंगना जब छोटी उम्र में घर वालों की खिलाफत करके दिल्ली आई, तब तक उनके लिए अभिनेत्री बनने का रास्ता बहुत मुश्किल रहा। मगर पहले गैंगस्टर, फिर तनु वेड्स मनु और क्वीन ने उन्हें अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। कई खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजरी कंगना अपने जीवन की उपलब्धियों में कई लोगों के योगदान की बात करती हैं।

कंगना का मानना है कि अपने अकेले दम पर कोई भी इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। वे कहती हैं, 'इंसान की जिंदगी में कई लोग होते हैं, जो किस्मत को संवारते हैं। माता, पिता, गुरु से शुरू होने वाला ये सिलसिला चलता जाता है। आज जो शब्दावली मैं बोल भी पा रही हूं, तो उसमें कई लोगों का योगदान है। जब मैं अभिनय के क्षेत्र में आई, उस वक्त अनुराग बसु मेरे करियर में अहम साबित हुए, जिन्होंने मुझे गैंगस्टर जैसी फिल्म दी और फिर विकास बहल जैसे फिल्मकार जिन्होंने क्वीन से मुझे सफलता दिलाई। पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री पर स्लो डाउन के बादल मंडरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्मों का बजट, स्टार्स की फीस जैसे फैक्टर्स में यदि सुधार नहीं हुआ, तो फिल्म उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। इस पर कंगना कहती हैं, 'फिल्म इंडस्ट्री को उठना तो पड़ेगा ही। मुझे याद है, आज से दस साल पहले मैं और शेखर कपूर (फिल्मकार) किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, कंगना जिसके हाथ में कैमरा या मोबाइल होगा, वो एक फिल्म बनाएगा। उस वक्त मुझे लगा था कि हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। मुझे उनकी बात जंची नहीं थी। मगर आज देखिए, आज इंटरनेट पर लोग दो-दो मिनट की फिल्म बना रहे हैं। कोई ट्रेन में चढ़ा हुआ है, तो कोई दूर - दराज के गांव में बैठी कोई महिला दूध दुहना सिखा रही है, कोई खाना पकाना सिखा रहा है, तो कोई मेकअप टिप्स दे रहा है और आप सभी इस सिस्टम में पूरी तरह से एंगेज हो गए हैं। दूसरों की क्या कहूं, मेरे खुद के माता-पिता आज रील्स में इतना बिजी हैं। आज रिलेटेबल रोल्स खत्म होते जा रहे हैं। पुष्पा जैसा मजदूर आपने कब देखा था? शायद अमिताभ बच्चन जी के दौर में।'

जॉन सर सही मायनों में कूल हैं

कंगना की नई फिल्म को लेकर एक दिलचस्प बात ये है कि इसका शीर्षक जॉन अब्राहम के पास रजिस्टर था, मगर उन्होंने खुशी-खुशी इसे कंगना को दे दिया। इस पर कंगना कहती हैं, 'इंसान वहीं मांगता है, जहां उसे उम्मीद होती है। जॉन सर के साथ शूटआउट एट वडाला की थी। उनके बारे में जो कहा जाता है कि वे अपने काम से काम रखते हैं और सही मायनों में कूल गाय है। उनके साथ एक कमाल का कंफर्ट था। मैं इसे दोस्ती तो नहीं कहूंगी, क्योंकि दोस्ती की अलग-अलग परिभाषा होती है। जो मैंने उनका बर्ताव देखा, तो पाया कि वे अपने काम से काम रखते हैं, मगर ऐसा भी नहीं हैं कि दुनिया-जहान से ला-ताल्लुक हैं। अप्रोचेबल हैं, रीचेबल हैं,, अगर हैं अपनी दुनिया में। मैंने जब भी उनके साथ काम, किया, मुझे बहुत मजा आया। हमारी इस फिल्म का नाम पहले नर्सेज ऑफ कामा था, मगर शीर्षक में वो बात नहीं आ पा रही थी। तब टाइटल आया, भारत भाग्य विधाता, मगर फिर पता चला कि ये शीर्षक तो जॉन सर के पास है। जाहिर है, वो निर्माता भी हैं, तो एक निर्माता कई सालों तक पैसे जमा कर करके अपने टाइटल को सुरक्षित रखता है। मुझे लगा मैं इस शीर्षक के लिए किसी तरह से उन्हें मना ही लूंगी, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मेरे कहने भर से उन्होंने मुझे दे दिया। उनका दिल बहुत बड़ा है।'



संक्षिप्त समाचार

अहमदाबाद में भक्ति का महाकुंभः राष्ट्रसंत आचार्य पद्मसागरजी का ऐतिहासिक चातुर्मास 15 जुलाई से

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। प्रभु महावीर की उज्ज्वल और समृद्ध श्रमण परंपरा के महान संवाहक, युगदृष्टा, राष्ट्रसंत और प्राचीन श्रुत-तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्यदेव श्री पद्मसागर सूरीश्वरद्धद्ध महाराजा आदि ठाणा का आगामी पावन चातुर्मास इस वर्ष धर्मनगरी अहमदाबाद की धरा पर होने जा रहा है। सूरिपद सुवर्ण वर्ष से मंडित यह ऐतिहासिक चातुर्मास शेला-स्काय सिटी के प्रांगण में भक्ति, संयम और अध्यात्म का एक नया इतिहास रचेगा।



15 जुलाई की सुबह होगा गुरु भगवंतों का भव्य नगर प्रवेश

इस पावन चातुर्मास के अंतर्गत आगामी 15 जुलाई को सुबह ठीक 06:45 बजे राष्ट्रसंत आचार्य श्री पद्मसागर सूरीश्वरजी महाराजा के साथ पूज्य आचार्य श्री प्रशांतसागर सूरीश्वरजी महाराज साहेब आदि गणि-श्रमण-श्रमणी भगवंतों का नगर में भव्य मंगल प्रवेश होगा। अनेक गुरु भगवंतों की पावन निश्रा और गरिमामयी उपस्थिति में होने वाले इस प्रवेश महोत्सव को लेकर जैन समाज सहित पूरे अहमदाबाद के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और हर्ष की लहर है।

सूरिपद सुवर्ण वर्ष के उपलक्ष्य में वोरा परिवार और जैन संघ का विशेष उपक्रम

अध्यात्म के इस महापर्व को भव्य रूप देने के लिए 'श्री मुनिसुव्रतस्वामी स्काय सिटी जैन संघ, शेला' और 'श्री संघोक मातुश्री सरयूबेन हसमुखभाई वोरा परिवार' मुख्य रूप से प्रयासरत हैं। वोरा परिवार और स्थानीय जैन संघ के विशेष सहयोग से शेला-स्काय सिटी के प्रांगण को इस पावन चातुर्मास और सुवर्ण वर्ष महोत्सव के लिए पूरी तरह सजाया जा रहा है।

देशभर के श्री संघों को आमंत्रण, चार महीनों तक होंगे विशेष अनुष्ठान

महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए पूज्य श्री प्रशांत सागरजी महाराज ने बताया कि आगामी चार महीनों के दौरान शेला के इस पावन प्रांगण में अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बड़े आयोजन किए जाएंगे। गुरु भगवंतों के इस मंगल प्रवेश के पावन अवसर पर देश भर के सभी जैन श्री संघों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। साथ ही, आयोजन समिति और वोरा परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से इस ऐतिहासिक प्रवेश महोत्सव में शामिल होकर दर्शन-वंदन का पुण्य लाभ लेने की भावभीनी विनती की है। मुख्य स्थलः श्री nity शांति भवन (आनंद ओलिगन्स के पास) मंगल प्रवेश समयः 15 जुलाई, सुबह 06:45 बजे, विशेष

रिपोर्टः दीपक जैन (महानगर मेट्रो न्यूज)

पुर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू के नेतृत्व में आर-पार की लड़ाई का ऐलान

महानगर मेट्रो ब्यूरो

राजनांदगांव/डोंगरगांव। कृषि भूमि विवाद को लेकर पिछले 16 वर्षों से न्याय की मांग कर रहे किसानों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि उधार देने के नाम पर धोखाधड़ी कर उनकी कृषि भूमि हड़प ली गई। इस मामले में वर्ष 1976 के संबंधित अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। किसानों का कहना है कि पूर्व में तहसीलदार छुरिया और एसडीएम (राजस्व) डोंगरगांव की जांच में भी रजिस्ट्री किसानों की इच्छा के विरुद्ध कराए जाने और ट्रैक्टर छीने जाने जैसी बातें सामने आई थीं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। किसानों ने बताया कि मामले में पिछले दो वर्ष नौ माह के दौरान 96 से अधिक पेशियां हो चुकी हैं, जबकि आरोपित पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। हाल ही में एसडीएम (राजस्व) के स्थानांतरण के बाद किसानों में निराशा और आक्रोश बढ़ गया है। इस बीच खुज्जी की पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 13 जुलाई 2026 की सुनवाई में उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में अपने परिवारों के साथ विधानसभा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे।



ईरान का खौफः ट्रंप ने बीच रास्ते में बदला विमान, कतर का जेट छोड़ पुराने 'एयरफोर्स वन' में बैठे

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौटते समय ट्रंप ने कतर द्वारा गिफ्ट में दिए गए नए बोइंग 747-8 जेट की बजाय अपने पुराने 'एयरफोर्स वन' से उड़ान भरी। ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में एक छोटे से ठहराव के बाद विमान बदलने के इस फैसले ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया गया फैसला : द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद, यूएस सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप को विमान बदलने की सलाह दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसी विशेष खतरे की प्रतिक्रिया के बजाय केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया था। दरअसल, कतर की ओर से मिले नए विमान में अभी तक वे सभी एडवांस सुरक्षा फीचर्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जो मौजूदा 'एयरफोर्स वन' के बेड़े में मौजूद होते हैं।

हालांकि, वाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है कि नया विमान असुरक्षित है। वाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने स्पष्ट किया कि नया जेट 'उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल' से लैस है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 'ध्यान भटकाने और गुमराह करने' समेत अपने हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करता है।



ट्रंप बोले– 'मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर वन हूं' : विमान बदलने के पीछे सुरक्षा चिंताओं की बात को खुद ट्रंप ने भी खारिज कर दिया। ब्रिटेन से रवाना होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन हूं। ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में रुकने का असली मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैन्यकर्मियों को नया विमान दिखाना था। उन्होंने नए विमान को 'बिल्कुल नया और शानदार' बताते हुए सैन्यकर्मियों के साथ इसकी तस्वीरें भी साझा कीं और कहा कि वे लोग इसे देखकर काफी उत्साहित थे। पुरानी 'एयरफोर्स वन' से सफर करने के पीछे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 'पुरानी यादों को ताजा करने के लिए' ऐसा किया है।

खिड़कियों के ब्लाइंड्स बंद रखने का था निर्देश : इस यात्रा के दौरान पुरानी एयरफोर्स वन में सफर कर रहे पत्रकारों को फ्लाइट में खिड़कियों के ब्लाइंड्स (पर्दे) बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने बताया कि यह पाबंदी उनके निजी कंपार्टमेंट पर लागू नहीं थी। उन्होंने ईरान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा यहां मौजूद 'स्लीजबैग्स' की वजह से किया गया हो। विमान बदलने का यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका ने तेहरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ईरानी ठिकानों पर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बहरीन, कुवैत और कतर में मिसाइल हमले के चेतावनी सायरन बजने लगे। वहीं, कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने अपनी तरफ आ रही मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया है।

न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, ईरान से 'हॉर्मुज' पर नहीं हो पाई डीलः जेडी वेंस

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। पहले ईरान ने होर्मुज में जहाजों पर हमला किया और उसके बाद अब अमेरिका ने पलटवार किया। ईरान के बंदरगाहों पर हवाई हमले किए। इस बीच, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया है कि ईरान से शांति वार्ता की कोशिशों के बीच गोलीबारी कैसे शुरू हो गई और किस वजह से शांति को लेकर समझौता नहीं हो पाया। जेडी वेंस के मुताबिक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। उनकी पारंपरिक सेना को भी खत्म कर दिया गया है। हमारी डील की मुख्य बात यह थी कि अगर आप जहाजों पर गोलाबारी को रोक देंगे, तो हम अपनी नाकेबंदी को हटा लेंगे। लेकिन अगर आप जहाजों पर बम-गोले दागेंगे, तो हम पलटवार करेंगे और पहले से कहीं ज्यादा जोरदार पलटवार करेंगे। डील यही थी। लेकिन 24 घंटे पहले क्या हुआ? ईरान ने फिर से जहाजों पर गोलाबारी शुरू कर दी। हमारी डील बहुत सीधी-सादी है लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आगे कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बहुत साफ शब्दों में कहा कि Strait of Hormuz खुला रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी लोगों तक तेल और गैस की सप्लाई होती रहेगी। ट्रंप ने कहा कि वह अहम रास्ता जिससे विश्व की बहुत सारी ऊर्जा की सप्लाई होती है।

ट्रंप से रिश्ते सुधारने की कोशिशों पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोलीं- कोई पछतावा नहीं





रोम, एजेंसी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिशों पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों नेताओं के बीच ईरान मुद्दे पर सार्वजनिक बहस, निजी टिप्पणियां और सोशल मीडिया पर नोकझोंक चल रही है। इसके बावजूद मेलोनी अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं।

बुधवार को अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद मेलोनी ने ट्रंप के साथ संबंध बनाने के अपने प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण हमेशा इटली के राष्ट्रीय हितों और पश्चिमी देशों की एकता पर आधारित रहा है, न कि व्यक्तिगत राजनीति पर। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश पर पछतावा है, तो उन्होंने थोड़ा रुककर पानी पिया और दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की एकता में विश्वास के कारण उन्होंने यह राजनीतिक निवेश किया था। यह कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो उन्होंने केवल ट्रंप के आने पर अपनाई हो, बल्कि वह सभी नेताओं के साथ ऐसा ही करती हैं। कभी मेलोनी को यूरोप में ट्रंप का सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी माना जाता था। वह ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय शासनाध्यक्ष थीं।

उन्हें वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं। दरार तब शुरू हुई जब मेलोनी ने पोप लियो पर ट्रंप के हमलों की आलोचना की। पोप ने ईरान युद्ध की निंदा की थी। इसके बाद इटली ने पश्चिम एशिया जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली के सिगोनेला हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे रिश्ते और बिगड़ गए। ट्रंप ने ईरान पर इटली के रुख की आलोचना की और अमेरिका का समर्थन न करने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने मेलोनी को एक अच्छी इंसान भी बताया। विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने दावा किया कि फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनसे तस्वीर खिंचवाने की भीख मांगी थी।

ईरान ने किया बहरीन और कुवैत में हमले का दावा, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की भी बात कही



तेहरान, एजेंसी। अमेरिका द्वारा ईरान के दक्षिणी प्रांतों में किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बुशेहर प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी रूक्क9 ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी सेना के बयान में कहा गया, 'अमेरिकी दुश्मन द्वारा देश के दक्षिणी क्षेत्रों पर किए गए हमले के बाद हमारी सेना के ड्रोन ने बहरीन स्थित शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी बलों के ठिकानों पर हमला किया।' इससे पहले ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने नौसेना और एयरोस्पेस बलों के संयुक्त अभियान में बहरीन और कुवैत में 85 महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहरीन के सलमान पोर्ट, वहां तैनात अमेरिकी पांचवें बेड़े के ठिकानों और कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना की ओर से बुधवार तड़के किए गए।

पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा बलूचिस्तान तट के पास मिला

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार रात कराची पहुंचने से पहले लापता हो गया था। विमान शारजाह से कराची आ रहा था और उसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तानी खोजी दलों ने बलूचिस्तान के तट के पास अरब सागर में ओमारा से 53 समुद्री मील (लगभग 98 किलोमीटर) दूर विमान का मलबा बरामद कर लिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, रात 9:18 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी था। कंट्रोल रूम ने विमान को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन करीब तीन मिनट बाद उसका संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान कराची से 155 नॉटिकल मील (287 किमी) पश्चिम में ट्रैक किया गया। विमान के लापता होने के बाद अरब सागर में बड़े स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और अन्य एजेंसियां खोज अभियान में जुटी रही।



कहां मिला मलबा : करीब 12 घंटे के बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद ओमारा बंदरगाह से 53 नॉटिकल मील दक्षिण में विमान का मलबा बरामद किया गया। विमान ने मंगलवार शाम शारजाह से उड़ान भरी थी। संपर्क टूटने से ठीक पहले विमान की ओर से नेविगेशन सिस्टम में खराबी की रिपोर्ट दी गई थी।

कैसे हुआ हादसा : पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, रडार डेटा से पता चला है कि विमान ने अचानक अपनी दिशा में बड़ा बदलाव किया और फिर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात करीब 9:21 बजे कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील पश्चिम में विमान का रेडियो और रडार से संपर्क पूरी तरह टूट गया था।

रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन-कौन शामिल : हादसे का अलर्ट मिलते ही बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अरब सागर में चलाए जा रहे इस अभियान में पाकिस्तान नेवी के युद्धपोत 'पीएनएस जुल्फिकार', नेवल सर्विलांस एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों के साथ-साथ मर्चेंट जहाजों को भी तैनात किया गया है।

ये 5 क्रू मेंबर हैं लापता : के2 एयरवेज ने बयान जारी कर बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वे पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लापता क्रू मेंबर्स के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए हर संभव संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए।

हादसे की वजह पर एक्सपर्ट्स की राय : हालांकि विमान के गायब होने से पहले नेविगेशन सिस्टम में खराबी की बात सामने आई थी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर एआरवाई न्यूज से बातचीत में एविएशन एनालिस्ट इमरान असलम ने बताया कि अगर विमान का इंजन फेल भी हो जाए।

भारतीय इंजीनियर ने अमेरिका में की पत्नी की हत्या

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रह रहे एक 30 वर्षीय भारतीय इंजीनियर को यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंजीनियर पर नौ माह पहले अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि भारतीय इंजीनियर अविनाश नारने ने अपनी पत्नी रंजीता सब्बीनेनी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के शव की फोटो भारत में रह रही अपनी प्रेमिका को भी भेजी थी। पुलिस जांच के बाद हत्या का मामला साफ हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे रची भारतीय इंजीनियर ने साजिश : 27 अक्टूबर, 2025 को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारने ने पुलिस को फोन करके बताया कि उनकी पत्नी बाथरूम में बंद हैं और बाहर नहीं आ रही हैं। जब पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें सबिनेनी जमीन पर पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के दौरान, नारने ने पुलिस को बताया कि वह कुछ काम से अपार्टमेंट से बाहर गए थे। जब वह लगभग 40 मिनट बाद घर लौटे, तो उन्होंने सबिनेनी को बाथरूम में बंद पाया। हालांकि, अधिकारियों को नारने के बाहर रहने के दौरान घर में किसी और के घुसने का कोई सबूत नहीं मिला।

भारत में रहने वाली लड़की से थे प्रेम संबंध : अगले दिन, किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस ने सबिनेनी की मौत को हत्या करार दिया और कहा कि उनकी मौत गला घोंटे जाने के कारण दम घुटने से हुई थी। जांच से पता चला कि नारने का भारत में एक महिला के साथ कई वर्षों से रिश्ता था। उस महिला के साथ रिश्ते में रहते हुए ही, नारने की 5 जून, 2025 को सबिनेनी से शादी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि नारने की गर्लफ्रेंड भी उनकी शादी में शामिल हुई थी। हालांकि, सबिनेनी से शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता चलता रहा।

प्रेमिका को पत्नी के शव की तस्वीर भेजी : घटना वाले दिन, नारने ने अपनी गर्लफ्रेंड को कम से कम चार बार फोन किया था, जिसमें वह समय भी शामिल था जब उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह बंद बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि नारने ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी की लाश की तस्वीर भी भेजी थी। अधिकारियों को जांच में सबिनेनी के नारने को भेजे गए टेक्स्ट मैसेज भी मिले, जिनमें सब्बीनेनी ने कई बार शिकायत की थी कि नारने जो ड्रिंक्स उनके लिए बनाते थे, उनका स्वाद कड़वा होता था। अपनी मौत के दिन, उन्होंने अपने पति को मैसेज किया था कि उनके बनाए स्मूदी का स्वाद दवा और कफ सिरप जैसा था। 5 जुलाई को नारने पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है।

डीआर कांगो में इबोला वायरस का कहर जारी, 600 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा



किंशासा , एजेंसी। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इससे मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई है और 1,759 मामलों की पुष्टि हुई है। बुधवार देर रात जारी एक अपडेट में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अभी कुल 750 मरीज आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पतालों में 94 प्रतिशत बेड भरे हुए हैं। बुंडीबुग्यो इबोला वायरस से होने वाला यह प्रकोप, जिसे 15 मई को घोषित किया गया था, देश का 17वां इबोला प्रकोप है। इसने तीन प्रांतों - इतुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु - के 37 स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकोप से निपटने में कई बाधाएं आ रही हैं, जिनमें पोस्टमार्टम के लिए सैंपल लेने का समुदाय द्वारा विरोध, इलाज की अपर्याप्त क्षमता, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, सीमित सप्लाई, असुरक्षा और हथियारबंद समूहों से प्रभावित इलाकों तक सीमित पहुंच शामिल हैं। डीआरसी ने मई के मध्य में इस प्रकोप की घोषणा की थी। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि असुरक्षा, लोगों की आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव और अधूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण स्थिति से निपटना मुश्किल हो रहा है। इबोला वायरस से होने वाली एक दुर्लभ, गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी है।

यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फ्रूट बैट) से इंसानों में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों (बॉडी फ्लूइड्स) के सीधे संपर्क से फैलता है। इसमें अचानक फ्लू जैसे लक्षण और बुखार आता है। इससे शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। मई 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप की पुष्टि हुई थी। इसमें शामिल इबोला की बुंडीबुग्यो प्रजाति के लिए कोई वैक्सीन या खास इलाज नहीं है, हालांकि संभावित वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह प्रकोप एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हो रहा है: मानवीय संकट, दूरस्थ और घनी आबादी वाला क्षेत्र, साथ ही असुरक्षा और भारी जनसंख्या एवं व्यापारिक आवागमन। इसके लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। इनमें अचानक बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, तेज़ सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गंभीर मामलों में बिना किसी स्पष्ट कारण के ब्लीडिंग या शरीर पर निशान पड़ना शामिल है।

अब यूक्रेन खुद बनाएगा पैट्रियट एयर डिफेंस, रूस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक कूटनीति और युद्ध के मैदान की समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में आयोजित ह्वञ्ज शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को अब तक का सबसे बड़ा 'रक्षा तोहफा' दिया है।

यूक्रेन को मिला 'सुरक्षा कवच' का लाइसेंस : तुर्की में दुनिया के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का आधिकारिक लाइसेंस देगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि यूक्रेन न केवल अमेरिकी मदद पर निर्भर रहे, बल्कि अपनी धरती पर खुद इन मिसाइलों का निर्माण कर रूसी मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जेलेंस्की पिछले काफी समय से अमेरिका से इस तकनीक और लाइसेंस की मांग कर रहे थे, जिसे अब ट्रंप प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है।

क्यों 'जैकपॉट' है पैट्रियट सिस्टम : पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे घातक जमीन से हवा में मार करने वाली तकनीक माना जाता है। अमेरिकी दिग्गज कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन द्वारा विकसित यह सिस्टम किसी भी आधुनिक हमले को नाकाम करने में सक्षम है। इसकी विशेषताएं इसे बेहद खास बनाती हैं:



घातक मिसाइलें: पूरे सिस्टम में एक रडार सेट, एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर और घातक मिसाइलें शामिल होती हैं। वर्तमान में दुनिया के केवल 13 चुनिंदा देशों के पास ही यह तकनीक उपलब्ध है और अब यूक्रेन इस सूची में अपना नाम मजबूती से दर्ज करा रहा है।

'शांति की ओर एक बड़ा कदम' : इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ हुई बैठक को बेहद सकारात्मक बताया। जेलेंस्की ने कहा कि वे लोगों की जान बचाने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने के अमेरिकी फैसले के लिए आभारी हैं। उन्होंने जोर दिया कि इस बातचीत से यूक्रेन की स्थिति न केवल युद्ध के मैदान में मजबूत होगी, बल्कि यह कूटनीति और शांति की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

युद्ध की दिशा पर प्रभाव : यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का लाइसेंस मिलना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब तक यूक्रेन को इन मिसाइलों के लिए अमेरिका की सप्लाई चेन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह कदम स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में रूस-यूक्रेन संघर्ष एक नए और अधिक तकनीकी मोड़ पर पहुंचने वाला है।

Printed, Published and Owned by SARABJIT MAKAN and Printed by ILEVAN HASMUKHRAI THAKAR Printed at Jay Graphics & Printers, C/15, Vikram Chambers, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. and published from F/1 first floor, rajas apartment, near old railway crossing, maninagar east maninagar, Ahmedabad, Gujarat-380008. Editor SARABJIT MAKAN, Mo.: 9638877700, 9662420070.